साप्ताहिक

आरएनआई न. :– जेकेएचआईएन/25/ए0631

सबका जम्मू कश्मीर

हिन्दी • वर्ष: 2 • अंक: 2 • कठुआ, शनिवार 10 जनवरी 2026 • पृष्ठ: 16 • मूल्य: 5 रुपए

भारतीय एआई स्टार्टअप्स को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम करना चाहिए : प्रधानमंत्री मोदी

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डेटा गोप. नीयता सिद्धांतों पर आधारित हों।

उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्टअप्स को इस देश से वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम करना चाहिए, और यह भी बताया कि भारत किफायती एआई, समावेशी एआई और मितव्ययी नवाचार को विश्व स्तर पर बढ़ावा दे सकता है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ

एक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए, मोदी ने सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल विशिष्ट होने चाहिए और उन्हें स्थानीय और स्वदेशी सामग्री और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और कृ त्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमी देश के भविष्य के सह–निर्माता हैं।

अगले महीने आयोजित होने वाले शएआई फॉर ऑलरू ग्लोबल इम्पैक्ट चौलेंजश शिखर सम्मेलन के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले 12 भारतीय एआई स्टार्टअप ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और अपने विचारों और कार्यों को प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान, मोदी ने समाज में परिवर्तन लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत अगले महीने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, जिसके माध्यम से देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाकर परिवर्तन लाने के प्रयास कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्टार्टअप और एआई उद्यमी भारत के

■ शेष पेज 2...

कांग्रेस वीबी-जी राम जी के बारे में झूठ फैला रही है : केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी

सबका जम्मू कश्मीर

बेंगलुरु : केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठ की कड़ी आलोचना की।

उन्होंने कहा कि गांवों में गारंटीशुदा नौकरियां छीने जाने के आरोप का कोई आधार नहीं है और दावा किया कि पूर्व यूपीए सरकार के रोजगार गारंटी कार्यक्रम में व्यापक भ्रष्टाचार था।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) के स्थान पर हाल ही में संसद द्वारा विकसित भारत रोजगार और आजीविका

■ शेष पेज 2...

जम्मू-कश्मीर सरकार प्रभावित मेडिकल छात्रों को अतिरिक्त सीटों के माध्यम से समायोजित करेगी : मुख्यमंत्री उमर

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेज बंद होने से प्रभावित छात्रों को अतिरिक्त सीटों के माध्यम से अन्य संस्थानों में समायोजित करके उनकी शिक्षा सुनिश्चित करेगी और उनकी शिक्षा पर कोई असर नहीं पड़ने देगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मानकों का पालन नहीं किया गया तो जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

अतिरिक्त सीटें प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त बनाई गई सीटें होती हैं।

अब्दुल्ला ने यहां पत्रकारों से कहा, "स्वास्थ्य मंत्री मेरे साथ यहां खड़ी हैं। कल वह सांबा में मेरे साथ थीं। हमने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है और जैसा कि मैंने कल सांबा में आदेश जारी होने के बाद कहा था, इन छात्रों ने छम्म्ज परीक्षा वैध तरीके से उत्तीर्ण की है। वे योग्य हैं।"

उन्होंने कहा, "उन्हें समायोजित करना हमारा कानूनी दायित्व है। हम उनके घरों के पास के कॉलेजों में अतिरिक्त सीटें बनाकर उन्हें समायोजित करेंगे

■ शेष पेज 2...

डॉ. जितेंद्र ने कर्मयोगी एआई क्लासरूम का शुभारंभ किया और नियम से भूमिका की ओर शासन प्रणाली में बदलाव को दोहराया

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी क्षेत्र में क्षमता निर्माण एक सतत और भूमिका–उन्मुख प्रक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण के लिए आज जो संस्थागत ढांचा लागू किया जा रहा है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिन्होंने गतिशील रूप से बदलती जिम्मेदारियों के लिए सरकारी अधिकारियों को तैयार करने हेतु एक संरचित तंत्र की आवश्यकता को पहचाना था।

ये टिप्पणियां क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) और कर्मयोगी भारत द्वारा इंडियाएआई मिशन के सहयोग से आयोजित क्षमता निर्माण के लिए एआईरू शासन का परिवर्तनष कार्यक्रम में की गईं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि शासन अब केवल नियमों और प्रक्रियाओं तक ही सीमित नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म षनियम से भूमिकाष की ओर एक निर्णायक बदलाव का

■ शेष पेज 2...

ऑपरेशन सिंदूर ने इस संदेश को और मजबूत किया कि लोगों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए : भारतीय वायु सेना प्रमुख

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : भारतीय वायु सेना के प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनसीसी कैडेटों के योगदान की सराहना की और कहा कि इस सैन्य कार्रवाई ने इस संदेश को और मजबूत किया कि जीवन केवल पैसा कमाने या व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के बारे में नहीं है, बल्कि देश के लिए कुछ करने के बारे में भी है।

दिल्ली छावनी में चल रहे राष्ट्रीय कैडेट कोर

(एनसीसी) गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेटों को संबोधित करते हुए, भारतीय वायु सेना प्रमुख ने उनसे आग्रह किया कि वे देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहें, चाहे वे बाद में सशस्त्र बलों में शामिल हों या अन्य व्यवसायों को अपनाएं।

उन्होंने असफलताओं से हतोत्साहित न होने बल्कि किसी भी बाधा से और भी मजबूत होकर उभरने का आग्रह किया, और शीर्ष पद तक पहुंचने की अपनी यात्रा का उदाहरण दिया।

सिंह ने कहा कि उन्हें भी अपने जीवन और करियर में असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे भारतीय वायु सेना के प्रमुख बनने तक पहुंचे, जिसे उन्होंने षभाग्य में लिखाष बताया।

उन्होंने कहा, ष्इसलिए, चाहे आप वर्दीधारी सैनिक हों या सैन्य नेता हों, या एक आम नागरिक हों, अपना सर्वश्रेष्ठ दें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।ष

भारतीय वायु सेना प्रमुख ने एनसीसी कैडेटों से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागरिक सुरक्षा गतिविधियों में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका ने कई लोगों को प्रेरित किया।

उन्होंने जोर देकर कहा, "ऑपरेशन सिंदूर ने काफी जागरूकता फैलाई है। जीवन में सिर्फ

■ शेष पेज 2...

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

शेष पेज 1 से.....

भारतीय एआई...

भविष्य के सह–निर्माता हैं और कहा कि देश में नवाचार और बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन दोनों की अपार क्षमता है। मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया के सामने एक ऐसा अनूठा एआई मॉडल पेश करना चाहिए जो श्मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्डश की भावना को दर्शाता हो। ये स्टार्टअप कई विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनमें भारतीय भाषा फाउंडेशन मॉडल, बहुभाषी एलएलएम, स्पीच–टू–टेक्स्ट, टेक्स्ट–टू–ऑडियो और टेक्स्ट–टू–वीडियो; ई–कॉमर्स, मार्केटिंग और व्यक्तिगत सामग्री निर्माण के लिए जनरेटिव एआई का उपयोग करके 3डी सामग्री; इंजीनियरिंग सिमुलेशन, सामग्री अनुसंधान और विभिन्न उद्योगों में डेटा–संचालित निर्णय लेने के लिए उन्नत विश्लेषण; स्वास्थ्य देखभाल निदान और चिकित्सा अनुसंधान आदि शामिल हैं।

एआई स्टार्टअप्स ने देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने एआई क्षेत्र की तीव्र वृद्धि और अपार भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नवाचार और तैनाती का केंद्र अब भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है।

नेताओं ने कहा कि भारत अब एआई विकास के लिए एक मजबूत और अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, जिससे देश वैश्विक एआई मानचित्र पर मजबूती से स्थापित हो गया है। बैठक में अवतार, भारतजेन, फ्रैक्टल, गण, जेनलूप, ज्ञानी, इंटेलीहेल्थ, सर्वम, शोध एआई, सोकेट एआई, टेक महिंद्रा और ज़ेंटेइक सहित भारतीय एआई स्टार्ट–अप के सीईओ, प्रमुख और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी बैठक में उपस्थित थे।

कांग्रेस वीबी–जी ...

मिशन (ग्रामीण) अधिनियम पारित किया गया है।

कांग्रेस का आरोप है कि नई योजना ग्रामीण भारत में रोजगार खत्म कर देगी और गांवों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। जोशी ने गुरुवार को इस आरोप का खंडन किया। "कांग्रेस झूठ बोल रही है कि वीबी–जी–राम जी योजना ग्रामीण रोजगार छीन लेगी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। वीबी–जी–राम जी संसद द्वारा पारित एक कानून है। इसलिए, यह कहना निराधार है कि इससे रोजगार कम होगा। हम 120 दिनों का रोजगार देने जा रहे हैं," उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले जोशी ने यहां पत्रकारों से कहा।

एमजीएनआरईजीए के तहत औसतन 50 दिनों का रोजगार दिया जाता था। "एमजीएनआरईजीए मांग आधारित नहीं बल्कि लक्ष्य आधारित थी। राज्य सरकारें कोई पैसा नहीं दे रही थीं। एमजीएनआरईजीए में व्यापक भ्रष्टाचार था और केंद्र सरकार के अनुदान का गबन किया जा रहा था। लक्ष्य पूरा न करने पर अधिक. ारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई," जोशी ने दावा किया।

उनके अनुसार, यूपीए सरकार के दौरान, एमजीएनआरईजीए के तहत 2012–13 में 40,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, लेकिन अगले वर्ष यह राशि घटकर केवल 33,000 करोड़ रुपये रह गई।

"राशि कम करने का क्या कारण है? आप (कांग्रेस) सिर्फ गैर–गंभीर और अंशकालिक राजनेताओं को खुश करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं," मंत्री ने आरोप लगाया। जोशी ने कहा कि 10 वर्षों में 853 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने आगे कहा कि 2012–13 तक 1,660 करोड़ मानव दिवस का श्रम सृजित हुआ था, जो अब बढ़कर 3,000 करोड़ मानव दिवस हो गया है, जिससे पता चलता है कि एनडीए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजित किए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 57 प्रतिशत हो गई है। जोशी ने जोर देकर कहा, "हम देश में बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से इसे उन्नत कर रहे हैं।"

सीएजी 2017 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 433 लाख फर्जी जॉब कार्ड थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एमजीएनआरईजीए का कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जम्मू–कश्मीर सरकार...

ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित न हो।"

उन्होंने कहा कि छात्रों को समायोजित करना कोई कठिन कार्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा, "हम इसे कर लेंगे।"

हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को मेडिकल कॉलेज बंद करने से छात्रों के भविष्य के साथ हुए अन्याय पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, "आज 50 सीटों में से 40 सीटें मुस्लिम छात्रों ने ले रखी थीं और इस पर आपत्ति जताई गई थी। लेकिन अगर समय के साथ इस कॉलेज में सीटों की संख्या धीरे–धीरे बढ़कर 400–500 हो जाती, तो संभव है कि भविष्य में 250–300 छात्र जम्मू से होते। अब वे छात्र कहां जाएंगे?" उन्होंने

जम्मू में भाजपा और अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि देशभर में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के इच्छुक छात्र संघर्ष करते हैं। उन्होंने कहा,

"शायद हम एकमात्र ऐसे स्थान हैं जहां हमें पूरी तरह से निर्मित मेडिकल कॉलेज मिला और फिर भी विरोध प्रदर्शनों के कारण इसे बंद कर दिया गया।"

अन्य कॉलेजों में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा किए गए निरीक्षणों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा कि निरीक्षण किसने किया और कॉलेज को कैसे मंजूरी दी गई।

उन्होंने कहा, "आपको विश्वविद्यालय और उसके सभी पदाधिकारियों से ऊपर से नीचे तक सवाल करना चाहिए – मेडिकल कॉलेज बनाने के बाद भी यह निरीक्षण में क्यों विफल रहा?"

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के इस दावे पर कि मानदंडों का पालन नहीं किया गया, अब्दुल्ला ने कहा कि यह मामला और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। "इस विश्वविद्यालय का प्रमुख कौन है और इसका कुलाधिपति कौन है? उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। सिर्फ मुझसे ही नहीं, उनसे भी पूछताछ कीजिए," उन्होंने कहा।

उन्होंने दोहराया कि अगर मानकों का पालन नहीं किया जाता है तो जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर आज भाजपा इस बात से खुश है कि विश्वविद्यालय मानकों का पालन करने में विफल रहा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या कार्रवाई की जाएगी? हम इन 50 छात्रों को समायोजित कर लेंगे, लेकिन छात्रों के भविष्य को हुए नुकसान के लिए किसी को तो जवाब देना ही होगा।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार संस्थान को दी गई वित्तीय सहायता वापस लेने का इरादा रखती है, तो अब्दुल्ला ने कहा, "विश्वविद्यालय को सहायता दी गई थी। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो पैसा देते हैं और फिर उसे वापस ले लेते हैं।"

बेरोजगारी और ज्यादा बोलने की आलोचना पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कभी किसी मुद्दे से पीछे नहीं हटे हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे बताइए कि मैं किस मुद्दे पर चुप रहा हूं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अगर किसी को और जवाब चाहिए तो विधानसभा सत्र आ रहा है। सदस्य वहां सवाल उठा सकते हैं और हम जवाब देंगे।"

डॉ. जितेंद्र ने कर्मयोगी...

प्रतिनिधित्व करता है, जिससे अधिकारी अपने कार्यों को अधिक स्पष्टता, जवाबदेही और परिणाम–उन्मुखता के साथ पूरा कर सकते हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि पारंपरिक प्रणालियां अधिकारियों को सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने में तो मदद करती हैं, लेकिन वे उन्हें उनके करियर के दौरान अक्सर कई क्षेत्रों में निभाई जाने वाली वास्तविक जिम्मेदारियों के लिए हमेशा तैयार नहीं करतीं।

मंत्री महोदय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सिविल सेवकों से हुई और धीरे–धीरे इसका विस्तार मंत्रालयों, विभागों और विभिन्न स्तरों के अधिकारियों तक हुआ। उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से इस पहल को नव–भर्ती अधिक. ारियों तक भी बढ़ाया गया है, जो रोजगार मेलों के दौरान जारी किए जाने वाले नियुक्ति पत्रों के साथ दिया जाता है। इससे अधिकारी अपनी सेवा की शुरुआत से ही वास्तविक प्रशासनिक चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं।

क्षमता निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण का उल्लेख करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती राधा चौहान के नेतृत्व में, पळव्ज प्लेटफॉर्म ने ।ᵖ सारथी, ।ᵖ ट्यूटर और ।ᵖ–आधारित क्षमता निर्माण योजनाओं जैसे ।ᵖ–संचालित उपकरणों को अपनाया है। उन्होंने कहा कि ये उपकरण मंत्रालयों और विभागों में व्यक्तिगत शिक्षण मार्ग, त्वरित योजना और बेहतर कार्यान्वयन को सक्षम बना रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासन परिणामों को मजबूत करने के लिए कृ त्रिम बुद्धिमत्ता को एक सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए, जो मानव बुद्धि के साथ मिलकर एक संकर दृष्टिकोण के माध्यम से काम करे।

इस कार्यक्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव श्रीमती रचना शाह सहित कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष राधा चौहान और कर्मयोगी भारत के अध्यक्ष श्री सुब्रमण्यम रामदोराई, केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षा जगत, उद्योग, प्रशिक्षण संस्थानों और विभिन्न मंत्रालयों की क्षमता निर्माण इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित थे।

कार्यशाला के संदर्भ को स्थापित करते हुए, कर्मयोगी भारत की सीईओ श्रीमती छवि भारद्वाज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पळव्ज सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता निर्माण के लिए मूलभूत डिजिटल अवसं. रचना के रूप में उभरा है, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी और 6.7 करोड़ से अधिक पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुके हैं। विभाग ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन (क्वच्ज) की सचिव श्रीमती रचना शाह ने इस बात पर बल दिया कि क्षमता निर्माण में प्रासंगिकता, समयबद्धता और वैयक्तिकरण में सुधार करके एआई पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक–केंद्रित शासन को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत कर सकता है, साथ ही नैतिक सुरक्षा उपायों और समावेशी पहुंच के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण ष्कर्मयोगी क्लासरूमष का शुभारंभ था, जो पळव्ज कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एक नई एआई–सक्षम सुविधा है, जिसे सिविल सेवकों के लिए प्रासंगिक, संवादात्मक और वैयक्तिकृत शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्यक्रम में अग्रणी एआई इकोसिस्टम भागीदारों द्वारा लाइव प्रदर्शन और विचार–विमर्श सत्र भी शामिल थे, जिसमें एआई ट्यूटर, एआई–संचालित क्षमता निर्माण योजनाएं, दक्षता मानचित्रण उपकरण और सार्वजनिक प्रशासन के लिए तैयार किए गए स्वदेशी एआई समाधानों का प्रदर्शन किया गया।

अपने संबोधन के समापन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशास. निक चुनौतियों, नागरिकों की अपेक्षाओं और तकनीकी उपकरणों के निरंतर विकास को देखते हुए शासन में सीखना एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक शक्तिशाली साधन के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि स्वयं में एक लक्ष्य के रूप में, और इसे हमेशा मानवीय विवेक और जिम्मेदारी द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय बुद्धिमत्ता को संयोजित करने वाला एक हाइब्रिड मॉडल भविष्य के लिए तैयार, उत्तरदायी और प्रभावी लोक प्रशासन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होगा।

ऑपरेशन सिंदूर ने...

पैसा कमाना या सिर्फ अपने लिए काम करना ही जरूरी नहीं है, देश के लिए कुछ करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।"

ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 7 मई, 2025 की सुबह–सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर अंजाम दिया गया था। यह कार्रवाई पिछले साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेटों ने आपातकालीन अभ्यास, रक्तदान शिविरों और अन्य नागरिक सुरक्षा गतिविधियों में सहायता की।

नामित मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने लद्दाख के उपराज्यपाल से मुलाकात की

सबका जम्मू कश्मीर

लेह : वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष कुंद्रा, जो 1 जनवरी को लद्दाख के मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हैं, ने मंगलवार को यहां उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात की और प्रमुख प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर विचार–विमर्श किया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

प्रवक्ता ने बताया कि कुंद्रा ने उपराज्यपाल सचिवालय में गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की और दोनों ने केंद्र शासित प्रदेश में शासन और विकास से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की।

उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने कुंद्रा को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं और लद्दाख में कुशल प्रशासन को और मजबूत करने में उनकी भूमिका पर विश्वास व्यक्त किया।

27 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारी का दिल्ली से लद्दाख तबादला करने का आदेश दिया और उन्हें 1 जनवरी, 2026 से या उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी पहले हो, लद्दाख के मुख्य सचिव के रूप में तैनात किया।

जीवनयापन को सुगम बनाने के लिए 2025 में शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा : डॉ. जितेंद्र

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2025 ऐसा वर्ष था जिसमें नागरिकों के जीवन स्तर को सुगम बनाने के उद्देश्य से शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक अनुकूल और कार्य–अनुकूल वातावरण का निर्माण किया गया।

यहां आयोजित वर्ष–समाप्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की वर्ष–समाप्ति की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्य शामिल हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष के दौरान किए गए सुधार न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत द्वारा निर्देशित थे, जिसमे प्रक्रियाओं को सरल बनाने, लंबित मामलों को कम करने और सरकार को अधिक उत्तरदायी और नागरिक–केंद्रित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि 2025 में शासन के परिणाम एक परिपक्व सुधार प्रक्रिया को दर्शाते हैं, जहां सार्वजनिक सेवा वितरण में ठोस सुधार लाने के लिए डिजिटल उपकरणों, संस्थागत नवाचार और मानव–केंद्रित दृष्टिकोणों को एक साथ लाया गया। शासन सुधार के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में क्षमता निर्माण पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी ने वर्ष के दौरान अपना विस्तार जारी रखा। पळव्–कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 1.45 करोड़ से अधिक पंजीकृत सरकारी कर्मचारी हैं, जो 23 भाषाओं में 4,155 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले ई–लर्निंग पाठ्यक्रम प्रदान करता है, और 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि पळव् मार्केटप्लेस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और सार्वजनिक नीति सहित सात विषयगत क्षेत्रों में विशेषज्ञता कार्यक्रम, और एआई सारथी, एआई ट्यूटर और एआई–सक्षम क्षमता निर्माण योजना उपकरण जैसे एआई–संचालित उपकरण जैसे नए फीचर सरकारी विभागों में भूमिका–आधारित कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के माध्यम से वर्ष के दौरान 8.73 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभान्वित किया गया, जिससे सेवा वितरण में ष्सेवा भावष् की भावना को बल मिला। छैब्ज् 2.0 फ्रेमवर्क का शुभारंभ और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में 29 कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब की स्थापना ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत किया है। मंत्री जी ने प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत पारदर्शिता और नागरिक–केंद्रित पहलों का भी उल्लेख किया, जिनमें मजबूत सुरक्षा सुविधाओं के साथ 2,899 सार्वजनिक प्राधिकरणों तक आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल का विस्तार और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के माध्यम से सेवा संबंधी शिकायतों के निवारण में सुधार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लखनऊ और गुवाहाटी में डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम और उन्नत बुनियादी ढांचे के साथ–साथ सर्किट बैठकों के माध्यम से विस्तारित क्षेत्रीय पहुंच के समर्थन से न्यायाधिकरण ने सितंबर 2025 तक 92.94 प्रतिशत की निपटान दर हासिल की है।

शिकायत निवारण सुधारों पर बोलते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली नागरिकों की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती रही है। 2025 के दौरान, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 20 लाख से अधिक सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा किया गया, जिनका औसत समाधान समय 15 दिन रहा। नागरिकों से 10 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं और शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए निगरानी तंत्र, प्रशिक्षण मॉड्यूल और राष्ट्रीय कार्यशालाएँ शुरू की गईं। उन्होंने राज्यों और जिलों में सुशासन सप्ताह और प्रशासन गाँव की ओर अभियान के पालन पर भी प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य मिशन–मोड दृष्टिकोण के माध्यम से प्रशासन को नागरिकों के करीब लाना है।

मंत्री ने कहा कि 84 मंत्रालयों और विभागों में लागू विशेष अभियान 5.0 का उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत बनाना और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना है।

इस अभियान में 11.6 लाख स्वच्छता केंद्रों को शामिल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 29.52 लाख फाइलें बंद या हटाई गईं, 233.75 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हुआ और वर्ष के दौरान कबाड़ निपटान से 833.92 करोड़ रुपये की आय हुई, जिससे सरकारी कार्यालयों में कार्यकुशलता और कार्यस्थल प्रथाओं में सुधार हुआ। पेंशनभोगी कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नवंबर 2025 में आयोजित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 अब तक का सबसे बड़ा अभियान था, जिसके तहत 2,000 जिलों, उप–मंडलों और शहरों में 1.68 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें से 1.01 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करके जमा किए गए। उन्होंने कहा कि भविष्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग का डिजिटलीकरण लगातार बढ़ रहा है, जबकि पेंशन संबंधी शिकायतों का निवारण किसी भी कैलेंडर वर्ष में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें 1.12 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। पेंशन अदालतों, सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाओं, अनुभव पुरस्कार और पेंशन संबंधी मुकदमों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला ने पेंशनभोगियों के लिए पहुंच और शिकायत निवारण को और मजबूत किया। इससे पहले, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने प्रस्तुति के दौरान मंत्रालय की प्राथमिकताओं और पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष के दौरान किए गए सभी सुधार पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक–केंद्रितता पर आधारित थे। उन्होंने कहा कि भर्ती सुधार, क्षमता निर्माण, शिकायत निवारण और पेंशन सेवाओं के क्षेत्र में मंत्रालय के प्रयास एक उत्तरदायी और भविष्य के लिए तैयार शासन प्रणाली के निर्माण की व्यापक दृष्टि से निर्देशित थे, जो विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।

ब्रीफिंग का समापन करते हुए मंत्री ने कहा कि 2025 में किए गए शासन सुधार और संस्थागत नवाचार आने वाले वर्षों में नीति और प्रशासनिक प्रथाओं को निर्देशित करते रहेंगे, क्योंकि मंत्रालय इन आधारों पर आगे बढ़ते हुए सेवा वितरण और सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास को और बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पर पशु चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी, डीएआरपीजी के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव और पीपीडब्ल्यू विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुबज्योति सेनगुप्ता उपस्थित थे, जो मंत्रालय के अंतर्गत तीनों विभागों की समन्वित भागीदारी को दर्शाता है।

इंडियन ऑयल ने लद्दाख में अब तक का सबसे बड़ा शीतकालीन स्टॉक पूरा किया

सबका जम्मू कश्मीर

चंडीगढ : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसने अब तक का सबसे बड़ा अग्रिम शीतकालीन भंडारण अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसके तहत वार्षिक शीतकालीन बंद से पहले लद्दाख को एक लाख किलोलीटर से अधिक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की गई है।

हर साल, जोजिला और रोहतांग जैसे ऊंचे पहाड़ी दर्रों पर भारी बर्फबारी के कारण दिसंबर से अप्रैल तक लद्दाख तक सड़क मार्ग से आवागमन बंद रहता है। इस अवधि के दौरान ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, इंडियन ऑयल सर्दियों के शुरू होने से पहले ही अग्रिम भंडारण करता है। कंपनी ने बताया कि यह आपूर्ति आम नागरिकों के साथ–साथ क्षेत्र में भारतीय सेना की रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। कंपनी ने बताया कि इंडियन ऑयल के टैंकर चालक और फील्ड टीमें दुनिया के सबसे कठिन ईंधन आपूर्ति मार्गों में से एक पर काम करते हैं, जो 7–8 दिनों में प्रति यात्रा 1,600–2,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। वे बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, जहां तापमान –20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, भारी बर्फबारी होती है, ऑक्सीजन का स्तर कम होता है और पहाड़ी सड़कें संकरी होती हैं। कंपनी ने बताया कि मौसम की स्थिति, अमरनाथ यात्रा के दौरान मौसमी भीड़भाड़ और सेब के परिवहन में भारी व्यस्तता के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग–44 पर बार–बार होने वाली रुकावटों से लॉजिस्टिक्स और भी प्रभावित हो रहा है। इस वर्ष 20 अप्रैल को रामबन जिले में बादल फटने से आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण इंडियन ऑयल के टैंकर अस्थायी रूप से फंस गए और छभ्–44 पर यातायात बाधित हो गया, जिससे संचालन में अतिरिक्त चुनौतियां आईं। कंपनी ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम घटना के बाद सुरक्षा संबंधी प्रतिबंधों और बिजली कटौती की स्थिति में भी आपूर्ति बनाए रखी गई। इंडियन ऑयल के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने टैंकर चालकों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया और उनके प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि कंपनी का आदर्श वाक्य, ष्पहले इंडियन, फिर ऑयल,ष् राष्ट्र की सेवा को प्राथमिकता देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी ने कहा कि इस रिकॉर्ड शीतकालीन भंडारण अभियान के साथ, इंडियन ऑयल ने देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण और दूरस्थ क्षेत्रों में ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका को फिर से स्थापित किया है।

रेलवे 14 जनवरी से रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की डिजिटल खरीद पर 3 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगा

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : रेल मंत्रालय 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की खरीद और किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान पर 3 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगा। वर्तमान में, यह रेलवन ऐप पर आर–वॉलेट भुगतान के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत कैशबैक देता है। ष्डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए, रेलवन ऐप पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट बुक करते समय 3 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, मंत्रालय ने 30 दिसंबर, 2026 को रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र को सॉफ्टवेयर सिस्टम में आवश्यक बदलाव करने के लिए संबोधित एक पत्र में लिखा। ष्3 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव 14.01.2026 से 14.07.2026 की अवधि के दौरान लागू रहेगा। ब्त्प्ै आगे की जांच के लिए मई में इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देगा,ष् इसमें आगे कहा गया है पत्र में स्पष्ट किया गया है कि रेलवन ऐप पर आर–वॉलेट के माध्यम से बुकिंग करने पर मौजूदा 3 प्रतिशत कैशबैक जारी रहेगा।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

विकसित भारत की नींव हैं : सत शर्मा

चक में बागवानी जागरूकता और विकास शिविर आयोजित ब्राह्मण, अखनूर

सबका जम्मू कश्मीर

अखनूर : बागवानी विभाग, जम्मू ने चक में एक व्यापक बागवानी जागरूकता और विकास शिविर का आयोजन किया ब्राह्मणा , अखनूर , मोदी सरकार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए खेती और खेती को मजबूत करने पर जोर देने के अनुरूप है । इस कैंप का मकसद मॉडर्न बाग. वानी के तरीकों को बढ़ावा देना, फसल अलग-अलग तरह के खेती को बढ़ावा देना, और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए बनाई गई सरकारी स्कीमों के बारे में जागरूकता फैलाना और किसाना. ` को मज़बूत बनाकर विकसित भारत के विज़न में योगदान देना था।

सत शर्मा, सांसद (राज्यसभा) और जम्मू-कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष, जुगल किशोर शर्मा, सांसद (लोकसभा) सभा), मोहन लाल भगत , विधायक अखनूर , गुल सईद , डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, जम्मू, आरके कोतवाल , चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जम्मू, और संदीप शर्मा, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर (भ्क्व), अखनूर , और दूसरे अधिकारी और स्टेकहोल्डर्स कैंप में खास तौर पर मौजूद थे।

प्रोग्राम की शुरुआत अखनूर ब्लॉक में फलों की पैदावार बढ़ाने के मकसद से बागवानी की को. शिशों के ओवरव्यू से हुई । इसमें बड़ी संख्या में किसानों और कम्युनिटी के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

सभा को संबोधित करते हुए सत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मोदी ने खेती और बागवानी को ग्रामीण विकास की नीतियों के केंद्र में रखा है। उन्होंने कहा कि एक विकसित भारत के लिए एक मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था ज़रूरी है, और यह सिर्फ़ किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक जानकारी और फाइनेंशियल मदद देकर ही हासिल किया जा सकता है। सत शर्मा ने किसानों से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (भ।क्व) और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर (डप्क्भ) जैसी योजनाओं का पूरा इस्तेमाल करने की अपील की, जो सब्सिडी, अच्छी क्वालिटी का प्लांटिंग मटीरियल, टेक्निकल गाइडेंस और मार्केट लिंकेज देती हैं। उन्होंने सस्टेनेबल इनकम और लंबे समय तक रोज़ी-रोटी की सुरक्षा पक्का करने के लिए ज़्यादा कीमत वाली फलों की फसलों में डाइवर्सिफिकेशन पर ज़ोर दिया।

जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार का विज़न किसाना. ` को एग्री -एंटरप्रेन्योर बनाने पर फोकस है।

उन्होंने जम्मू में बागवानी की बहुत ज़्यादा संभावनाओं पर ज़ोर दिया और ड्रैगन फ्रूट की खेती की ज़ोरदार वकालत की, इसे इस इलाके के लिए ज़्यादा कमाई वाली, कम पानी वाली फसल बताया। उन्होंने किसानों को नई फसलें अपनाने और अपनी कमाई बढ़ाने के लिए सरकारी मदद लेने के लिए बढ़ावा दिया।

मोहन लाल भगत ने इस पहल की तारीफ़ की और कहा कि ऐसे कैंप ज़मीनी स्तर पर किसानों और एक्सपर्ट्स के बीच की दूरी को कम करते हैं। उन्होंने कहा कि अखनूर चुनाव क्षेत्र में पैदावार को बेहतर बनाने और किसानों की इनकम को मज़बूत करने के लिए समय पर गाइडेंस, अच्छी क्वालिटी की जानकारी और स्कीमों के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है।

डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और एचडीओ अखनूर समेत फील्ड-लेवल अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों को ट्रेनिंग, मार्केट एक्सेस और स्कीम लागू करने में मदद करने के डिपार्टमेंट के कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया ।

जिला प्रभारी विनय महाजन , जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, किसान बोर्ड के पूर्व वीसी दलजीत चिब , वरिष्ठ नेता परदुमन सिंह, मनमोहन सिंह, जगदीश भगत और दूसरे लोग कैंप में मौजूद खास लोगों में से थे।

खेलो इंडिया ने ग्लोबल लेवल पर भारत के खेल जगत को बढ़ावा दिया : बलबीर

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन और पूर्व वाइस चेयरमैन बलबीर राम रतन ने कहा है कि खेलो इंडिया विज़न ने भारत की स्पोर्ट्स की उम्मीदों को शानदार ग्लोबल अचीवमेंट्स में बदल दिया है, जिससे देश इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में एक मज़बूत और कॉन्फिडेंट ताकत बन गया है। बलबीर राम रतन ने कहा कि 2025 में भारत की खेलों में हालिया सफलता एक लगातार और अच्छी तरह से बने स्पोर्ट्स मूवमेंट का नतीजा है, जो टैलेंट की पहचान, हाई-क्वालिटी ट्रेनिंग और लंबे समय तक एथलीट डेवलपमेंट को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसी पहल ने एक ठोस इकोसिस्टम बनाया है जहाँ युवा टैलेंट को सिस्टमैटिक तरीके से निखारा जाता है और ग्लोबल लेवल पर बेहतर करने के मौके दिए जाते हैं। दुनिया के खेलों में भारत के बढ़ते रुतबे पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने 2025 में बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन की ओर इशारा किया, जिसम. ` महिला वर्ल्ड क्रिकेट कप, प्ब्ब मेन्स चौंपियंस ट्रॉफी, ज्20 वर्ल्ड कप, स्क्वैश वर्ल्ड कप और कबड्डी वर्ल्ड कप शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन जीतों ने न केवल देश को बहुत गर्व महसूस कराया है, बल्कि भारत की खेल की गहराई, कॉम्पिटिटिवनेस और प्रोफेशनलिज़्म के बारे में दुनिया भर की सोच को भी बदल दिया है।

बलबीर राम रतन ने स्वदेशी और उभरते खेलों में भारत के दबदबे पर भी ज़ोर दिया, और पुरुष और महिला खो-खिलाड़ी दोनों में शानदार जीत का ज़िक्र किया। खो वर्ल्ड कप। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां साफ दिखाती हैं कि कैसे पारंपरिक भारतीय खेल, जब खेलो इंडिया जैसे स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म के ज़रिए सपोर्ट किए जाते हैं, तो दुनिया भर में पहचान बना सकते हैं। उन्होंने पिकलबॉल वर्ल्ड कप में भारत के अच्छे प्रदर्शन पर भी ज़ोर दिया , जो देश की नए ज़माने के खेलों में ढलने की काबिलियत और बढ़ती मौजूदगी को दिखाता है।

भारत की खेल यात्रा में सबको साथ लेकर चलने पर ज़ोर देते हुए, बलबीर राम रतन ने डेफलंपिक्स में 20 मेडल जीतने की कामयाबी की तारीफ़ की और इसे खेलों में बराबर मौके और सबको साथ लेकर चलने की तरक्की का एक मज़बूत उदाहरण बताया। उन्होंने यूथ स्पोर्ट्स मुकाबलों में मिले 48 मेडल की ओर भी ध्यान दिलाया और उन्हें सबसे ऊँचे लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार युवा टैलेंट की मज़बूत पाइपलाइन का साफ़ इशारा बताया। भारतीय बॉक्सर्स के परफॉर्मेंस की तारीफ़ करते हुए, बलबीर राम रतन ने कहा कि वर्ल्ड बॉक्सिंग फ़ाइनल में 20 मेडल जीतना हिम्मत, अनुशासन और वर्ल्ड-क्लास कोचिंग के असर को दिखाता है। उन्होंने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने, ज़मीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने और शहरी और ग्रामीण, दोनों बैकग्राउंड के एथलीटों को लगातार सपोर्ट देने के लिए खेलो इंडिया पहल को क्रेडिट दिया, जिससे ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पर बिना डरे मुकाबला करने के लिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा देने वाली भूमिका को भी माना। मोदी ने कहा कि बधाई संदेशों, जीतने वाली टीमों के साथ मीटिंग और सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के ज़रिए प्रधानमंत्री का एथलीटों से पर्सनल जुड़ाव ने उनका हौसला काफी बढ़ाया है और युवा भारतीयों को स्पोर्ट्स में बड़े सपने देखने के लिए मोटिवेट किया है।

खराब मौसम और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर छह उड़ानें रद्द कर दी गईं

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण बुधवार को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर हवाई अड्डे पर आने-जाने वाली कुल छह उड़ानें रद्द कर दी गईं।

यह घटना जम्मू और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में छाए घने को. हरे के बीच हुई है।

श्रीनगर हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा जारी एक पोस्ट के अनुसार, मौसम संबंधी कारणों से इंडिगो की एक, एयर इंडिया की तीन और एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान रद्द की गई, जबकि स्पाइसजेट की एक उड़ान परिचालन संबंधी कारणों से रद्द की गई। पोस्ट में रद्द उड़ानों की सूची के साथ लिखा है, "कृपया ध्यान दें कि परिच. ालन और मौसम संबंधी कारणों से आज की सभी उड़ानें फिलहाल रद्द हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि हवाई अड्डे जाने से पहले संबंधित एयरलाइन से अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें। आगे की जानकारी मिलते ही साझा की जाएगी। असुविधा के लिए खेद है और आपके सहयोग की सराहना करते हैं।"

श्रीनगर हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा जारी एक अलग पोस्ट में कहा गया है, "यात्रियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त के अलावा, एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान नौवीं 1271/1272, जिसका आगमन अनुमानित समय 1345 बजे और प्रस्थान समय 1420 बजे है, जम्मू में खराब मौसम की आशंका के कारण आज रद्द कर दी गई है। असुविधा के लिए हमें खेद है और हम यात्रियों को सलाह देते हैं कि वे पुनः बुकिंग और सहायता के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।"

भारतीय विमानन प्राधिकरण ने एक सलाह जारी कर यात्रियों से उड़ान की स्थिति पर नज़र रखने और सामान्य समय से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने का आग्रह किया है।

"घने कोहरे के कारण कम दृश्यता उत्तरी भारत के कुछ हवाई अड्डों पर परिचालन को प्रभावित कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप उड़ानों में देरी हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सीधे अपनी एयरलाइन से उड़ान संबंधी अपडेट प्राप्त करें और सामान्य समय से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें। ।।ᑭ की टीमें यात्रियों की सहायता और सुरक्षित, सुचारू परिचालन सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों पर मौजूद हैं," ।।ᑭ के बयान में कहा गया है।

इससे पहले मंगलवार सुबह, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी शहर में छाए घने कोहरे के कारण उड़ान परिचालन बाधित हुआ था। कोहरे के कारण हवाई अड्डे पर लगभग 60 आगमन और 58 प्रस्थान रद्द कर दिए गए, और दिल्ली जाने वाली 16 उड़ानों को अन्य

कश्मीर घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बहुस्तरीय सुरक्षा; जाँच और गश्त तेज की गई

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नव वर्ष समारोह के मद्देनजर घाटी भर में, विशेषकर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इन स्थानों पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर घाटी में, विशेषकर नव वर्ष समारोह के आयोजन स्थलों पर, जाँच और निगरानी बढ़ा दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदुओं पर अतिरिक्त चौकियाँ स्थापित की गई हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए घाटी की महत्वपूर्ण सड़कों पर गश्त, क्षेत्र नियंत्रण अभियान और अचानक निरीक्षण बढ़ा दिए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है और सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर उच्च स्तर की सतर्कता बरती जा रही है।

शांति और परस्पर निर्भरता की राजनीति : आज के विश्व के लिए अनिवार्य आवश्यकता

कृ आई. डी. खजुरिया

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस विश्व व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, उसका मूल उद्देश्य थाकृयुद्ध की विभीषिका से मानवता को बचाना, राष्ट्रों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना तथा शांति, न्याय और समानता पर आधारित एक वैश्विक प्रणाली का निर्माण करना। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ (न्छ), अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य बहुराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई। किंतु समय के साथ यह स्पष्ट होता गया कि विश्व व्यवस्था का संचालन शांति और सह–अस्तित्व के बजाय शक्ति, टकराव और वर्चस्व की राजनीति से होने लगा।

आज की वैश्विक राजनीति में हम देखते हैं कि कुछ शक्तिशाली राष्ट्र अपने स्वार्थों को सर्वोपरि रखते हुए प्रकृति, मानवता और कमजोर देशों का शोषण कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, बाजारों पर एकाधिकार, हथियारों का व्यापार और युद्ध की राजनीति को आर्थिक लाभ से जोड़ दिया गया है। इस प्रक्रिया में न केवल पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुँची है, बल्कि मानव जीवन भी निरंतर खतरे में पड़ा हुआ है। युद्ध अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहे; वे आर्थिक प्रतिबंधों, साइबर हमलों, वैचारिक संघर्षों और राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में भी सामने आ रहे हैं।

यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि अनेक बार अंतरराष्ट्रीय कानूनों, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और वैश्विक सहमति को दरकिनार कर एकतरफा निर्णय लिए जाते हैं। कुछ राष्ट्र स्वयं को विश्व का निर्णायक मानते हुए "एक व्यक्ति के शासन" जैसी मानसिकता से काम करते हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ न तो तर्कसंगत हैं और न ही नैतिक। वे केवल अस्थिरता, भय और अविश्वास को जन्म देती हैं। इतिहास साक्षी है कि शक्ति के बल पर थोपी गई शांति कभी स्थायी नहीं होती।

यदि आज विश्व के विवेकशील नागरिक, बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठन और शांतिप्रिय राष्ट्र एकजुट होकर शांति और परस्पर निर्भरता की राजनीति के लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो मानवता को ऐसे विनाश का सामना करना पड़ सकता है, जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बमों से भी अधिक भयानक होगा। आधुनिक हथियारों की मारक क्षमता इतनी अधिक हो चुकी है कि एक छोटी–सी चूक भी संपूर्ण सभ्यता को संकट में डाल सकती है।

शांति की राजनीति का अर्थ केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि यह सहिष्णुता, सह–अस्तित्व, स्वीकृति और आपसी सम्मान पर आधारित व्यवहारिक मानसिकता की माँग करती है। इसका मतलब है कि राष्ट्र अपने मतभेदों को संवाद, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के माध्यम से सुलझाएँ। परस्पर निर्भरता की राजनीति यह स्वीकार करती है कि आज कोई भी देश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है; वैश्विक चुनौतियाँकृजैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और आर्थिक असमानताकृसभी को मिलकर ही सुलझानी होंगी।

इस संदर्भ में हथियारों की होड़ पर गंभीर पुनर्विचार आवश्यक है। दुनिया भर में अरबों डॉलर हथियारों और बमों पर खर्च किए जाते हैं, जबकि वही संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण पर लगाए जा सकते हैं। यह समय की मांग है कि सभी प्रकार के हथियारों, बमों और मिसाइलों के विनाश की दिशा में ठोस और ईमानदार पहल की जाए। यह कार्य आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहींकृयदि राजनीतिक इच्छाशक्ति और जन–दबाव मौजूद हो।

शांति की स्थापना केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। इस धरती का प्रत्येक नागरिक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमें युद्धोन्मादी भाषा और नफरत फैलाने वाले विचारों का विरोध करना होगा, शांति, संवाद और मानवता के मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में अपनाना होगा। मीडिया, शिक्षा और सामाजिक मंचों के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

अंततः, यह समझना आवश्यक है कि मानवता का भविष्य टकराव की राजनीति में नहीं, बल्कि शांति और परस्पर निर्भरता की राजनीति में सुरक्षित है। यदि हम आज सही दिशा में कदम नहीं उठाते, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए आइए, हम सब मिलकर शांति, सह–अस्तित्व और आपसी सम्मान पर आधारित विश्व व्यवस्था की मांग करें और उसे साकार करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएँ।

शांति और परस्पर निर्भरता की राजनीति को कायम रखना ही मानवता का एकमात्र मार्ग है।

किरपान मोर्चा 1937 : धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई

तरनजीत सिंह

1937 का किरपान मोर्चा सिख इतिहास में धार्मिक स्वतंत्रता और अस्मिता की रक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह आंदोलन सिखों के उस मूल धार्मिक अधिकार को स्थापित करने के लिए आरंभ किया गया था, जिसके तहत वे किरपान धारण और धारण कर सकते हैं। किरपान केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि सिख धर्म में आस्था, मर्यादा, आत्मसम्मान और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने के दायित्व का प्रतीक है। खालसा पंथ में दीक्षित सिखों के लिए किरपान पाँच ककारों में से एक अनिवार्य धार्मिक चिह्न है, जिसे किसी भी परिस्थिति में त्यागा नहीं जा सकता।

ब्रिटिश शासन के दौरान लागू भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1878 (इंडियन आर्म्स एक्ट, ग्) के अंतर्गत किरपान को एक हथियार की श्रेणी में रखा गया था। इस कानून के अनुसार किसी भी प्रकार के हथियार को रखने या धारण करने के लिए सरकारी लाइसेंस आवश्यक था। इस प्रावधान ने सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार किया, क्योंकि उनके लिए किरपान धारण करना कानून नहीं बल्कि धर्म का आदेश है। सिख समुदाय ने इस कानून को न केवल धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध माना, बल्कि इसे अपने आत्मसम्मान और पहचान पर हमला भी समझा।

इसी पृष्ठभूमि में किरपान मोर्चे का जन्म हुआ। यह आंदोलन मूल रूप से अहिंसक था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट संदेश देना था कि सिख अपने धार्मिक अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। हजारों सिखों ने जानबूझकर पूर्ण आकार की किरपान धारण कर सार्वजनिक रूप से निकलना शुरू किया और गिरफ्तारी दी। यह एक प्रकार का सत्याग्रह था, जिसमें कानून तोड़ा गया, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लिया गया। सिखों का मानना था कि यदि कानून धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हो, तो उसका नैतिक रूप से विरोध करना आवश्यक है।

इस आंदोलन को जनसमर्थन दिलाने और विचारों के प्रचार–प्रसार के लिए 'किरपान बहादुर' नामक

एक समाचार पत्र भी शुरू किया गया। यह पत्र आंदोलन की आवाज़ बना और सिख समुदाय के भीतर एकता और जागरूकता पैदा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके माध्यम से सिखों ने यह स्पष्ट किया कि किरपान का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने का नैतिक बल प्रदान करना है।

किरपान मोर्चे का पहला बड़ा चरण 1920 के दशक के आरंभ में देखने को मिला। लंबे संघर्ष और लगातार गिरफ्तारियों के बाद मार्च 1922 में पंजाब सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने यह घोषणा की कि सिखों को किरपान पहनने, रखने और धारण करने के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा। यह समझौता सिख समुदाय के लिए एक बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत थी। हालांकि, इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में समय–समय पर किरपान को लेकर विवाद और टकराव होते रहे।

1937 का उल्लेख इसी निरंतर संघर्ष की ओर संकेत करता है। इस समय तक भी कुछ स्थानों, विशेषकर दिल्ली जैसे क्षेत्रों में, सिखों के किरपान धारण के अधिकार को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया था। कई बार स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा किरपान को लेकर आपत्तियाँ उठाई जाती थीं, जिससे सिखों को अपने अधिकारों के लिए फिर से संगठित होना पड़ा। 1937 में हुए घटनाक्रमों के दौरान सिख प्रतिनिधिमंडलों ने प्रशासन से बातचीत की और अपने धार्मिक अधिकारों की पुनः पुष्टि की मांग की।

यह संघर्ष केवल औपनिवेशिक शासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने सिखों के इस लंबे संघर्ष और धार्मिक संवेदनशीलता को समझते हुए संविधान में विशेष प्रावधान शामिल किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि सिखों द्वारा किरपान पहनना और धारण करना उनके धर्म के पालन का अभिन्न हिस्सा है और इसे अवैध नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान न केवल सिख समुदाय के लिए, बल्कि भारत की बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक पहचान के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

किरपान मोर्चा इस बात का प्रतीक है कि धार्मिक स्वतंत्रता केवल कागजी अधिकार नहीं, बल्कि संघर्ष और बलिदान से प्राप्त होती है। इस आंदोलन ने यह सिद्ध किया कि शांतिपूर्ण और संगठित प्रतिरोध के माध्यम से भी बड़े से बड़े कानूनों को बदला जा सकता है। सिख समुदाय ने अपने आचरण से यह दिखाया कि किरपान शक्ति का प्रतीक अवश्य है, लेकिन उसका मूल संदेश रक्षा, न्याय और करुणा है, न कि हिंसा।

आज जब भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित है, तब 1937 के किरपान मोर्चे जैसे आंदोलनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह हमें याद दिलाते हैं कि संविधान में दर्ज अधिकार किसी एक दिन में नहीं मिले, बल्कि उनके पीछे इतिहास, संघर्ष और असंख्य लोगों का त्याग छिपा है।

किरपान मोर्चा सिखों की धार्मिक चेतना, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता प्रेम का जीवंत उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक रहने की प्रेरणा देता रहेगा।

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

न्यायपालिका व पत्रकारिता दोनों सवालों के घेरे में

राज कुमार

लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभकृविधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिकाकृके साथ–साथ पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है। इन स्तंभों की मजबूती से ही लोकतंत्र संतुलित और जीवंत रहता है। किंतु हाल के वर्षों में न्यायपालिका और पत्रकारिता, दोनों ही अपने–अपने दायित्वों, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर सवालों के घेरे में आ गई हैं। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य के लिए भी गंभीर संकेत देती है।

न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक और नागरिकों के अधिकारों की अंतिम ढाल माना जाता है। आम आदमी की अपेक्षा रहती है कि अदालतें निष्पक्ष, त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करेंगी। परंतु न्यायिक प्रक्रिया में बढ़ती देरी, लंबित मामलों का अंबार, और कभी–कभी विवादित फैसलों ने जनता के मन में असंतोष को जन्म दिया है। वर्षों तक चलने वाले मुकदमे पीड़ितों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से तोड़ देते हैं। न्याय में देरी को न्याय से वंचित किए जाने के समान माना जाता है, लेकिन यह सच्चाई आज भी बार–बार सामने आती है।

इसके अतिरिक्त, न्यायपालिका पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि वह आम जनता की अपेक्षाओं से कटती जा रही है।

कुछ मामलों में शक्तिशाली वर्गों को राहत और कमजोर पक्षों को लंबी कानूनी लड़ाइयों में उलझते देखा गया है। हालांकि यह कहना भी उचित नहीं होगा कि पूरी न्यायपालिका पक्षपाती है, क्योंकि अनेक जज आज भी साहसिक और ऐतिहासिक

फैसले देकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं। फिर भी, व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता।

दूसरी ओर, पत्रकारिता, जिसे समाज का दर्पण कहा जाता है, वह भी आज गंभीर संकट से गुजर रही है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्ता से सवाल पूछना, सच को सामने लाना और जनता की आवाज बनना है।

लेकिन टीआरपी की दौड़, कॉरपोरेट दबाव और राजनीतिक प्रभाव ने इसके स्वरूप को काफी हद तक बदल दिया है। कई बार खबरों को सनसनीखेज बनाया जाता है, तथ्यों की पुष्टि के बिना आरोप लगाए जाते हैं और "ब्रेकिंग न्यूज़" की होड़ में जिम्मेदारी पीछे छूट जाती है।

फेक न्यूज और प्रायोजित खबरें पत्रकारिता की साख को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें तेजी से फैलती हैं और मुख्यधारा मीडिया भी कई बार बिना जांच के उन्हें आगे बढ़ा देता है।

इससे समाज में भ्रम, तनाव और अविश्वास का माहौल बनता है। जब मीडिया खुद सवालों के घेरे में आ जाता है, तो जनता के पास भरोसेमंद सूचना का स्रोत सीमित हो जाता है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है।

न्यायपालिका और पत्रकारिता के बीच एक और समानता यह है कि दोनों पर "अभिजात वर्ग" तक सीमित रहने का आरोप लगता रहा है। आम जनता की वास्तविक समस्याएंकृगरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यकृअक्सर हाशिये पर चली जाती हैं, जबकि बड़े नाम, बड़े घोटाले और राजनीतिक बयान सुर्खियों में छाए रहते हैं। इससे जनसरोकार कमजा. र पड़ते हैं और व्यवस्था से लोगों का भरोसा डगमगाने लगता है।

हालांकि, इस निराशाजनक तस्वीर के बीच उम्मीद की किरणें भी हैं। न्यायपालिका में समय–समय पर सुधार के प्रयास हुए हैं, जैसे ई–कोर्ट, फास्ट ट्रैक अदालतें और लोक अदालतें। वहीं पत्रकारिता में भी कई ईमानदार पत्रकार और स्वतंत्र मंच आज भी सच्चाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि न्यायपालिका अपनी प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी, त्वरित और जनोन्मुखी बनाए। वहीं पत्रकारिता को आत्ममंथन करते हुए अपने मूल सिद्धांतोंकृसत्य, निष्पक्षता और जनहितकृकी ओर लौटना होगा। सरकार, समाज और संस्थानोंकृतीनों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इन स्तंभों को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत किया जाए।

अंततः, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए यह अनिवार्य है कि न्यायपालिका पर जनता का विश्वास अडिग रहे और पत्रकारिता निडर होकर सच का साथ दे। यदि ये दोनों स्तंभ सवालों के घेरे में ही बने रहे, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होना तय है। इसलिए समय रहते सुधार, जवाबदेही और नैतिकता को प्राथमिकता देना ही एकमात्र रास्ता है।

राज कुमार(मुख्य संपादक)
सबका जम्मू कश्मीर हिंदी साप्ताहिक समाचार

धर्म की रक्षा में गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान

रविंदर राठौड़

गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के नौवें गुरु थे। उनका जन्म वर्ष 1621 में अमृतसर में हुआ था। वे छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद जी के सबसे छोटे पुत्र थे। बचपन से ही उनका स्वभाव गंभीर, शांत और चिंतनशील था। जहाँ उस समय के अन्य राजकुमार और सिख योद्धा खुले रूप से शस्त्र विद्या, नेतृत्व और युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहे थे, वहीं गुरु तेग बहादुर जी का झुकाव ध्यान, साधना, काव्य और आत्म–अनुशासन की ओर अधिक था। उनके लिए वास्तविक शक्ति बाहरी शस्त्रों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मिक दृढ़ता में निहित थी।

युवावस्था में भी वे एकांत, वैराग्य और आत्मचिंतन को प्राथमिकता देते थे। इसी कारण कुछ समय तक वे सार्वजनिक जीवन से दूर रहे और लोगों को उनका जीवन साधारण तपस्वी जैसा प्रतीत होता था। किंतु यह मौन और साधना भविष्य में आने वाले महान बलिदान की तैयारी थी। 1665 में गुरु हरकृष्ण जी के ज्योति–जोत समाने के बाद, गुरु तेग बहादुर जी को सिखों का नौवाँ गुरु घोषित किया गया। यह वह समय था जब भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर गहरा संकट मंडरा रहा था।

मुगल सम्राट औरंगज़ेब के शासनकाल में कट्टर धार्मिक नीतियाँ लागू की जा रही थीं। विशेष रूप से हिंदुओं पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बढ़ गया था। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार चरम पर थे। उनसे इस्लाम स्वीकार करने या भारी दंड भुगतने को कहा जा रहा था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, धार्मिक कर्मकांडों पर रोक लगाई जा रही थी और भय का वातावरण व्याप्त था। ऐसे कठिन समय में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर साहिब पहुँचा और उनसे सहायता की गुहार लगाई।

कश्मीरी पंडितों की पीड़ा सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने इसे केवल किसी एक समुदाय की समस्या

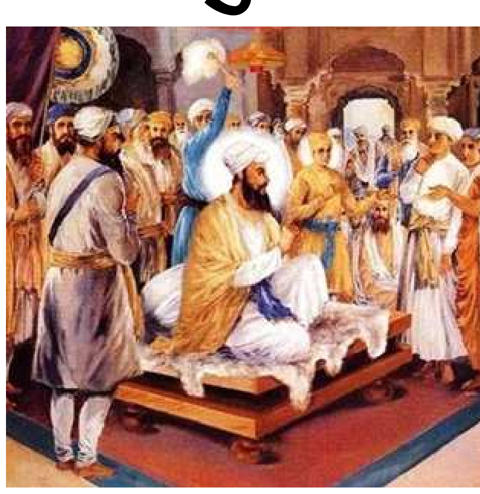

नहीं माना, बल्कि इसे मानव अंतरात्मा और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा प्रश्न समझा। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म की रक्षा केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए की जानी चाहिए। उन्होंने एक ऐसा नैतिक निर्णय लिया, जो भारतीय इतिहास में अद्वितीय था। उन्होंने कहा कि यदि औरंगज़ेब उन्हें इस्लाम स्वीकार कराने में सफल हो जाए, तो कश्मीरी पंडित भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यदि वे अपने धर्म पर अडिग रहें, तो किसी पर भी जबरन धर्म थोपने का अधिकार नहीं रहेगा।

इस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी ने स्वयं को इस संघर्ष के केंद्र में रख दिया। वे जानते थे कि इसका परिणाम मृत्यु भी हो सकता है, फिर भी उन्होंने सत्य और धर्म के मार्ग से पीछे हटने से इंकार कर दिया। उन्हें दिल्ली बुलाया गया और 1675 में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ उनके तीन प्रमुख शिष्यकृभाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयालाकृभी थे। इन सभी को अमानवीय यातनाएँ दी गईं, ताकि गुरु जी अपने धर्म से विचलित हो जाएँ, किंतु वे अडिग रहे।

गुरु तेग बहादुर जी ने किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया। अंततः नवंबर 1675 में दिल्ली के चाँदनी चौक में उनका शीश काट दिया गया। यह बलिदान इसलिए अद्वितीय था क्योंकि उन्होंने अपने धर्म की नहीं, बल्कि दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। भारतीय इतिहास में यह पहली बार था जब किसी संत ने परधर्म के लोगों के अधिकारों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया।

इसी महान त्याग के कारण गुरु तेग बहादुर जी को "हिंद दी चादर" कहा जाता है, अर्थात भारत की ढाल। उनका जीवन यह सिखाता है कि साहस हमेशा शोर, हथियार या हिंसा के रूप में प्रकट नहीं होता। कभी–कभी साहस शांति, संयम और सिद्धांतों पर अडिग रहने में दिखाई देता है। उन्होंने बिना तलवार उठाए, अपने आत्मबल से अत्याचार को चुनौती दी।

गुरु तेग बहादुर जी एक महान कवि और दार्शनिक भी थे। उनके 115 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित हैं। उनकी वाणी में संसार की नश्व. रता, अहंकार की व्यर्थता, भय, मोह और मृत्यु की अनिवार्यता पर गहन चिंतन मिलता है। उनकी रचनाएँ मनुष्य को आंतरिक स्वतंत्रता और आत्मिक संतुलन का मार्ग दिखाती हैं। वे कहते हैं कि जिसने मृत्यु और अपमान के भय पर विजय पा ली, वही वास्तव में मुक्त है।

उनके बलिदान का प्रभाव सिख इतिहास पर गहरा पड़ा। इसने सिखों की सामूहिक चेतना को नया स्वरूप दिया और अत्याचार के विरुद्ध संगठित प्रति. रोध की नींव रखी। उनके पुत्र, गुरु गोबिंद सिंह जी, ने इसी पृष्ठभूमि में आगे चलकर खालसा पंथ की स्थापना की, जिसने सिखों को संत–सिपाही के रूप में संगठित किया।

गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रसंग 1666 का भी है। कश्मीरी पंडितों की रक्षा के प्रयासों के दौरान मुगल प्रशासन ने उन्हें दिल्ली में नज़रबंद कर दिया था। उन्हें लगभग दो महीने तक नजरबंदी में रखा गया। इस दौरान आम जनता से उनका संपर्क सीमित था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक साधना और संकल्प में कोई कमी नहीं आई। अंततः राजा राम सिंह के हस्तक्षेप के कारण 11 जनवरी 1666 को उन्हें नजरबंदी से मुक्त कर दिया गया।

रिहाई के बाद गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा पुनः आरंभ की। वे विभिन्न नगरों और क्षेत्रों में गए, लोगों को निर्भयता, नैतिकता और धर्म की स्वतंत्रता का संदेश दिया। मई 1666 तक वे पटना पहुँचे, जहाँ उन्होंने संगत को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। यही पटना आगे चलकर उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मस्थली बना।

गुरु तेग बहादुर जी का संपूर्ण जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि सच्ची शक्ति बाहरी सत्ता में नहीं, बल्कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता में होती है। उन्होंने यह दिखाया कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड भी किसी को झुकाने का प्रयास करे, तब भी यदि मनुष्य अपने विवेक और सिद्धांतों पर अडिग रहे, तो वही वास्तविक विजय है। उनका जीवन आज भी मानवता को यह प्रेरणा देता है कि धर्म, स्वतंत्रता और नैतिकता की रक्षा के लिए शांत किंतु अटल प्रतिरा. ध सबसे प्रभावशाली अस्त्र होता है।

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

संपादकीय

बिरसा मुंडा बलिदान

संपादक – राज कुमार

जैसे–जैसे हम 9 जनवरी 1900 को डोंबारी बुरु में हुई दुखद घटनाओं की 126वीं सालगिरह के करीब आ रहे हैं, यह ज़रूरी है कि हम उन शहीदों को याद करें जिन्होंने आज़ादी और सम्मान के लिए अपनी जान दे दी। झारखंड की डोंबारी बुरु की खून से सनी पहाड़ियाँ हमारे आदिवासी बहादुरों की अटूट भावना का एक शाश्वत प्रमाण हैं। उनका बलिदान, जो अक्सर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, न केवल याद किए जाने बल्कि राष्ट्रीय पहचान का हकदार है। झारखंड के खूंटी ज़िले में स्थित बुरु पहाड़ियाँ सिर्फ़ एक भौगोलिक पहचान से कहीं ज़्यादा हैं; वे आदिवासी साहस और वीरता की अदम्य भावना का प्रतीक हैं। यह प्रतीकवाद 1899 में भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए क्रांतिकारी आंदोलन में गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसे उलगुलान या ष्महान उथल–पुथलष के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा, एक दूरदर्शी आदिवासी नेता, ने अपने लोगों को दमनकारी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकजुट किया, जिसने उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया था, उनके संसाधनों का शोषण किया था, और शोषणकारी भूमि नीतियों और मिशनरी प्रभावों के माध्यम से उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता को खत्म कर दिया था। उलगुलान सिर्फ़ एक विद्रोह नहीं था; यह स्व–शासन का एक गहरा दावा था, जो बिरसा के नारे में समाहित थारू ष्अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जानाष (महारानी का राज खत्म हो, और हमारा राज शुरू हो)। डोंबारी बुरु इस प्रतिरोध का केंद्र बन गया, जहाँ हज़ारों मुंडा रणनीति बनाने और शाही ताकत के खिलाफ मज़बूती से खड़े होने के लिए इकट्ठा हुए। आज, ये पहाड़ियाँ लचीलेपन, एकता और अन्याय के खिलाफ विरोध के कालातीत आदिवासी लोकाचार का प्रतीक हैं, जो पीढ़ियों को अपनी विरासत को बनाए रखने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। डोंबारी बुरु नरसंहार की ओर ले जाने वाली घटनाएँ 1890 के दशक के अंत में बढ़ते तनाव के बीच हुईं। बिरसा मुंडा के आंदोलन ने तब गति पकड़ी जब आदिवा. सियों ने ब्रिटिश ज़मींदारी व्यवस्था और वन कानूनों का विरोध किया, जिसने उन्हें उनकी पैतृक ज़मीनों से वंचित कर दिया था। 5 जनवरी 1900 को, बिरसा के अनुयायियों की औपनिवेशिक ताकतों से झड़प हुई, जिसमें एटकेडीह में दो पुलिस कांस्टेबल मारे गए। दो दिन बाद, 7 जनवरी को, उन्होंने खूंटी में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप एक और कांस्टेबल की मौत हो गई। बड़े पैमाने पर विद्रोह के डर से, अंग्रेजों ने कैप्टन एच.एच. डाल्टन के नेतृत्व में सेना जुटा ली। 9 जनवरी को, 400 से ज़्यादा निहत्थे मुंडा आदिवासी दृ पुरुष, महिलाएँ और बच्चे दृ एक मीटिंग के लिए शांतिपूर्वक डोम्बारी बुरु में इकट्ठा हुए थे। बिना किसी चेतावनी के, ब्रिटिश सेना ने गोलियाँ चला दीं, जिससे गोलियों की बौछार हुई और पहाड़ी कत्लगाह बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पास की ताजना नदी खून से लाल हो गई थी, क्योंकि सैकड़ों लोगों को बेरहमी से मार दिया गया था। इस अत्याचार में 400 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, जो 1919 के कुख्यात जलियाँवाला बाग हत्याकांड से लगभग दो दशक पहले हुआ था और यह स्वदेशी आबादी के खिलाफ अपनी क्रूरता में कहीं ज़्यादा खूनी था। इसे सही ही ष्झारखंड का जलियाँवाला बागष कहा जाता है क्योंकि, अमृतसर की त्रासदी की तरह, इसने उपनिवेशवाद का क्रूर चेहरा दिखाया, जिसमें एक सीमित जगह पर निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया, जहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं था। मुंडा खुद कुछ समय के लिए पकड़े जाने से बच गए थे, लेकिन 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को 25 साल की उम्र में रांची जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। जब देश भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है, तो यह सही समय हो सकता है कि डोम्बारी बुरु को न केवल 1900 के शहीदों के लिए, बल्कि पूरे भारत के सभी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। ऐसा स्मारक एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में काम करेगा, जो आगंत. ुकों को भारत की स्वतंत्रता में आदिवासी समुदाय के अक्सर भुला दिए गए योगदान के बारे में शिक्षित करेगा। इसमें संग्रहालय, स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र शामिल हो सकते हैं जो आदिवासी इतिहास को उजागर करें, स्वदेशी कहानियों को मुख्यधारा की स्वतंत्रता कहानी में एकीकृत करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दें। यह मान्यता दूरदराज की पहाड़ियों और जंगलों में किए गए बलिदानों का सम्मान करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि आदिवासी प्रतिरोध की विरासत भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। डोम्बारी बुरु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना भारत के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि हो सकती है, जो 1769 में रघुनाथ महतो के विद्रोह से लेकर 1940 के दशक में जयपाल सिंह मुंडा की वकालत तक फैली हुई है। जंगल महल के एक नेता रघुनाथ महतो ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, स्थानीय समुदायों को एक उग्र विद्रोह में संगठित किया जिसने शुरुआती औपनिवेशिक प्रभुत्व को चुनौती दी।

अमेरिका के इशारे पर न थिरकने वाले देश कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें!

कमलेश पांडे

अंतर्राष्ट्रीय जगत में आर्थिक और तकनीकी दृष्टिकोण से संपन्न अमेरिका अपनी श्डीप स्टेट खलनीतिश के बल पर दुनिया का दादा बन चुका है। चूंकि जी–7 के देश उसके मजबूत हाथ हैं, इसलिए ब्रिक्स देशों की औकात उससे खुलेआम उलझने की आजतक नहीं बन पाई है। आखिर पहले भारत के पास–पड़ोस में, फिर ईरान में और अब बेनेजुएला के दास्तान जो चुगली कर रही हैं, उसके वैश्विक मायने तो यही हैं। अब अगला नम्बर शायद कम्बोडिया का आएगा, जिसे ट्रंफ ने ताजा धमकी दी है।

देखा जाए तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्वप्नद्रष्टा डॉनल्ड ट्रंफ उनकी मुद्रा को चुनौती दिलवाने वाले, यदा कदा उनको आंखें दिखाने वाले रूस–चीन के मजबूत समर्थकों के एक एक कर रीढ़ तोड़ने और इसी झांसे में जांबाज भारत को धमकाकर अपने खेमे में मिलाने के लिए सधी चालें चलना शुरू कर चुके हैं। डीप स्टेट से जुड़े लोगों की मानें तो आगे अमेरिका अभी बहुत कुछ करने वाला है। इस बात का संकेत कभी न्यूयॉर्क के महापौर ममदानी और भारतीय–अमेरिकी आशा जडेजा के इशारों से चलता है। ममदानी जहां खुलेआम स्वजातीय भारतीय देशद्रोहियों के पक्ष में खत लिख रहे हैं, वहीं आशा जडेजा ने तो खुलेआम भारत को रूसी सम्बन्धों पर नसीहत दी है।

मतलब साफ है कि दुनिया भर में ब्रिक्स और रिक (रूस–भारत–चीन) देशों का हौव्वा खड़ा करके रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कभी अलग अलग और कभी संयुक्त मंच पर अमे. रिका विरोधी शेखी बघारते आये हैं, उनके ग्लोबल साउथ के सपनों पर बम्बार्डिंग शुरू हो चुकी है। यदि डीप स्टेट के समक्ष ट्रंफ ने घुटने टेके हैं तो अब उन्हें रणनी. तिक बुलंदी भी मिल रही है। रूस को यूक्रेन में, भारत को पाकिस्तान–बंगलादेश से और चीन को दक्षिण चीन सागर में उलझाए रखने की जो खतरनाक अमेरिकी साजिश है, उसकी काट अभी किसी के पास नहीं है।

अभी तक एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में अमेरिका को कमजोर करने की जो चालें चीन व भारत की तरफ से अलग अलग चली जा रही थीं, इनकी हवा निक. ालने के लिए ही अमेरिका ने अपना आक्रामक तेवर दिखा दिया है, जिसे रो. कना अब किसी के बूते की बात नहीं। सच कहूं तो अमेरिका ने 19वीं शताब्दी से ही अपना विरोधी रहे कई देशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता परिवर्तन करवाए हैं, जिनमें मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका, एशिया और मध्य–पूर्व के देश शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि वाकई ये हस्तक्षेप अक्सर डीप स्टेट के इशारे पर सीआईए के माध्यम से गुप्त अभियानों, सैन्य आक्रमणों या समर्थन के जरिए हुए। इस बात को स्पष्ट करने वाले कुछ प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण निम्नलिखित हैं, जो अमेरिका के विरोधी देशों को अपने हद में रहने की खुली नसीहत देते हैं। चाहे अमेरिका का पुराना प्रतियोगी सोवियत संघ हो या फिर उसके अवशेष पर खड़ा रूस और उसका नया वैश्विक पार्टनर चीन, अमेरिका के नापाक इरादों में कभी मजबूत बाधक नहीं बन पाए। मसलन, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इनकी अंतर्राष्ट्रीय विवशता जगजा. हिर हो चुकी है। यह स्थिति जहां एकध्रुवीय विश्व की अमेरिका परिकल्पना और उसकी दादागिरी को परिपुष्ट करती है। वहीं, बहुध्रुवीय विश्व के पैरोकारों रूस, चीन और भारत आदि की नीतिगत बेचारगी की बखिया उधेड़ देती है। आइए अमेरिकी षड्यंत्र की साल दर साल मिली सफलता पर एक नजर डालते हैं। पहला, 1953 में ईरान में मोहम्मद मोसद्देघ की सरकार को अमेरिका के इशारे उखाड़ फेंका गया, और शाह को सत्ता में लाया। दूसरा, 1954 में ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति जैकोबो आरबेंज को हटाया गया और कार्लोस कास्टिलो आर्मास को सत्ता दी गई। तीसरा, 1963 में दक्षिण वियतनाम में राष्ट्रपति न्गो दिन्ह दीम की हत्या में सहायता दी। चतुर्थ, 1973 में चिली में सल्वाडोर एलेन्डे को उखाड़ा, और ऑगस्टो पिनोशे को सत्ता सौंपी। पांचवां, 1983 में ग्रेनाडा में सैन्य आक्रमण से सरकार बदली। छठा, 1989 में पनामा में मैनुअल नोरिएगा को हटाया। सातवां, 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन शासन को समाप्त कर उन्हें फांसी पर लटकवाया।

आठवां, 2011में लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के पतन में सहयोग दिया। नवाँ, 2026 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाया और कम्बोडिया के राष्ट्रपति को धमकाया। दरअसल, ये सूची प्रमुख मामलों तक सीमित है; जबकि कुल 80 से अधिक ज्ञात अमेरिकी हस्तक्षेप हुए हैं। हैरत की बात है कि अमेरिका के विरा. `धी देशों ने उसके सत्ता परिवर्तनों पर अक्सर खामोशी साधी या सीमित विरोध किया, क्योंकि सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक शक्तियों का असंतुलन उन्हें प्रत्यक्ष टकराव से रोकता था। सोवियत संघ जैसे प्रतिद्वंद्वी भी कई मामलों में अपनी सीमाओं के कारण सक्रिय हस्तक्षेप से परहेज करते रहे। वह सिर्फ भारत के मामले में ही कामयाब हो पाया, जहां अमे. रिका को पीछे हटना पड़ा। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं–

पहला, सैन्य श्रेष्ठतारू अमेरिका की परमाणु क्षमता और विशाल सेना ने विरो. धियों को जोखिम लेने से रोका, जैसे चिली (1973) में सोवियत संघ ने केवल निंदा की। दूसरा, आर्थिक निर्भरतारू कई देश अमेरिकी सहायता या व्यापार पर निर्भर थे, जिससे खुला विरोध अव्यवहारिक था। तीसरा, क्षेत्रीय प्रभावरू लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में अमेरिका का प्रभुत्व (मुनरो सिद्धांत) विरोध को अप्रभावी बनाता था। इसलिए सामरिक प्रतिक्रियाएं नगण्य रहीं। चतुर्थ, प्रतिसादरू विरोधी देशों ने खुद गुप्त सहायता दी, जैसे क्यूबा ने अंगोला में हस्तक्षेप किया। पांचवां, कूटनीतिरू संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाए गए लेकिन वीटो के कारण विफल रहे। छठा, आंतरिक प्राथमिकताएंरू चीन–रूस जैसे देशों की अपनी घरेलू चुनौतियां सक्रिय विरोध को सीमित करती रहीं।

हैरत की बात तो यह है कि अब रूस और चीन की तरह ही गुटनिरपेक्ष देश भारत को भी अमेरिकी नसीहत मिल रही है, जो गम्भीर बात है। गत दिनों जब वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले ने दुनिया का ध्यान खींचा है तो इस घटनाक्रम पर अलग–अलग तरह के रिएक्शन दुनियाभर से सामने आ रहे हैं। इसी बीच भारतीय–अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट आशा जडेजा मोटवानी ने वेनेजुएला के घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत पर तंज कसा है। आशा ने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने रूस से बहुत सारे हथियार खरीद रखे थे। हालांकि जब अमेरिका ने हमला किया तो ये हथियार काम नहीं आए। अमेरिकी सैनिक मादुरो तक पहुंचे और उनको बंधक बनाकर अमे. रिका ले आए। ऐसे में भारत को भी इससे सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि भारत के पास भी ज्यादातर रूस के ही हथियार हैं। आशा मोटवानी ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा, श्वेनेजुएला के रूसी मिलिट्री इक्विपमेंट अमेरिकी मिलिट्री के सामने कुछ सेकंड में टूट गए। उम्मीद है भारत देख रहा होगा। हमारे लिए यह जानना समझदारी होगी कि हमारी रोटी का कौन सा हिस्सा मक्खन लगा हुआ है, कौन हमारे ताकतवर दोस्त हैं और कौन नहीं।श अपनी पोस्ट में आशा ने भारतीय अमेरिकियों और भारतीय रूसियों की संख्या के अंतर को बढ़ा–चढ़ाकर बताते हुए एक गलत आंकड़ा दिया– श्भारतीय अमेरिकीरू 5,000,000। भारतीय रूसीरू 5। दरअसल, भारतीय मूल की वेंचर कैपिटलिस्ट आशा जडेजा हालिया समय में अमेरिका में चर्चा में आती रही हैं। हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि उनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भ्1–ठ पर अपना रुख बदला था। सिलिकॉन वैली की वेंचर कैपिटलिस्ट आशा डानाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा दान देने वाले लोगों में शुमार हैं। आशा जडेजा मोटवानी ने 200 से ज्ध्यादा टेक स्टार्टअप्स में निवेश किया है। उनके प्रमुख निवेशों में गूगल, पिंटरेस्ध्ट, यूलू, क्रेडलवाइज, एडहैक टेक्ध्नोलॉजीज, क्लिमैक्ध्टिक और नेशनल एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक नर्स प्रैक्ध्टीशनर्स शामिल हैं। आशा के पति राजीव मोटवानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

नव वर्ष के जश्न के दौरान स्विस आल्प्स के एक बार में लगी आग में दर्जनों लोगों के मारे जाने की आशंका है और लगभग 100 लोग घायल हुए हैं

सबका जम्मू कश्मीर

क्रान्स–मोंटाना (स्विट्जरलैंड) : पुलिस ने गुरुवार को बताया कि नव वर्ष के जश्न के दौरान स्विस आल्प्स के एक रिसॉर्ट शहर में एक बार में आग लगने के बाद दर्जनों लोगों के मारे जाने की आशंका है और लगभग 100 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकांश गंभीर रूप से घायल हैं

वालेस कैंटन के पुलिस कमांडर फ्रेडरिक गिस्लर ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि ले कॉन्स्टेलेशन नामक बार में ष्कई दर्जन लोगष् मारे गए। पीड़ितों की पहचान करने और उनके परिवारों को सूचित करने का काम चल रहा है, लेकिन ष्इसमें समय लगेगा और फिलहाल, आपको अधिक सटीक आंकड़ा देना जल्दबाजी होगी,ष् गिस्लर ने कहा, साथ ही यह भी कहा कि समुदाय ष्तबाहष् हो गया है। वैलिस कैंटन की अटॉर्नी जनरल बीट्रिस पिलौड ने कहा कि आग लगने के कारण का पता लगाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। विशेषज्ञ अभी तक मलबे के अंदर नहीं जा पाए हैं। पिल्लौद ने कहा, ष्किसी भी समय किसी भी प्रकार के हमले का कोई सवाल ही नहीं है।

उत्सव की एक शाम दुखद घटना में बदल जाती है

अधिकारियों ने इस आग को ष्फ्लैशओवर जनरलाइज़ष् कहा, जो अग्निशमन का एक शब्द है और यह बताता है कि कैसे आग लगने से ज्वलनशील गैसें निकल सकती हैं जो हिंसक रूप से प्रज्वलित हो सकती हैं और अंग्रेजी बोलने वाले अग्निशामकों की भाषा में इसे फ्लैशओवर या बैकड्राफ्ट कहा जाता है।

क्षेत्रीय सरकार के प्रमुख मैथियास रेनार्ड ने कहा, ष्आज शाम जश्न और एकजुटता का क्षण होना चाहिए था, लेकिन यह एक बुरे सपने में बदल गया। रेनार्ड ने बताया कि घायलों की संख्या इतनी अधिक थी कि क्षेत्रीय अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई और ऑपरेशन थिएटर जल्दी ही पूरी तरह से भर गए। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ितों की सहायता के लिए हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे, जिनमें कुछ अलग–अलग देशों के लोग भी शामिल थे।

स्विस राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार की ष्विचारधारा पीड़ितों, घायलों और उनके परिजनों के साथ है, जिनके प्रति वह अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।ष्

गुरुवार को परमेलिन ने राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला दिन शुरू किया, क्योंकि स्विट्जरलैंड सरकार के सात सदस्य बारी–बारी से एक वर्ष के लिए राष्ट्रपति पद संभालते हैं। पीड़ितों के परिवारों के प्रति सम्मान दिखाते हुए, उन्होंने गुरुवार दोपहर को प्रसारित होने वाला राष्ट्र के नाम अपना पारंपरिक नव वर्ष संबोधन स्थगित कर दिया, जैसा कि स्विस प्रसारकों एसआरएफ और आरटीएस ने बताया। फ्रांसीसी प्रसारक बीएफएमटीवी से बात करने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि लोग आग से बचने के लिए खिड़कियां तोड़ रहे थे, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे, और घबराए हुए माता–पिता यह देखने के लिए कारों से घटनास्थल की ओर दौड़ रहे थे कि कहीं उनके बच्चे अंदर फंसे तो नहीं हैं। उस युवक ने बताया कि उसने लगभग 20 लोगों को धुएं और आग से बाहर निकलने के लिए भागते हुए देखा और सड़क के दूसरी ओर से जो कुछ उसने देखा, उसकी तुलना किसी डरावनी फिल्म से की।

यह रिसॉर्ट शहर आल्प्स पर्वतमाला के मध्य में स्थित है।

ढलानों पर स्कीइंग करने वाले पर्यटकों से भरे इस क्षेत्र में, अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से आने वाले दिनों में सावधानी बरतने का आह्वान किया है ताकि ऐसी किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके जिसके लिए चिकित्सा संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है जो पहले से ही अत्यधिक व्यस्त हैं।

स्विस आल्प्स के मध्य में लगभग 3,000 मीटर (1.86 मील) की ऊँचाई पर स्थित स्की ढलानों के साथ, क्रान्स–मोंटाना स्विट्जरलैंड के स्की–प्रेमी वैलिस क्षेत्र के प्रमुख शीतकालीन खेल केंद्रों में से एक है। ज़र्मेट, वर्बियर और बर्फीली चोटियों और चीड़ के जंगलों में बसे अन्य रिसॉर्ट भी यहीं स्थित हैं, जो दुनिया भर से शीतकालीन खेल प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। यह रिसॉर्ट अल्पाइन स्कीइंग में विश्व कप सर्किट के शीर्ष रेस स्थलों में से एक है और फरवरी 2027 में दो सप्ताह तक चलने वाली अगली विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।

चार सप्ताह बाद, यह रिसॉर्ट मिलान कोर्टिना ओलंपिक में जाने से पहले सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला डाउनहिल रेसरों की अंतिम प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा, जो 6 फरवरी को शुरू होंगे।

क्रान्स–मोंटाना अंतरराष्ट्रीय गोल्फ का एक प्रमुख स्थल है। क्रान्स–सुर–सिएरे क्लब हर साल अगस्त में यूरोपियन मास्टर्स का आयोजन करता है, जो एक सुरम्य गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है और यहाँ से पहाड़ों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। ले कॉन्स्टेलेशन बार गोल्फ क्लब से लगभग 250 मीटर (273 गज) की दूरी पर स्थित है। क्रान्स–मोंटाना स्विट्जरलैंड के सिएरे से 5 किलोमीटर (3 मील) से भी कम दूरी पर स्थित है, जहां 2012 में बेल्जियम से आ रही एक बस के स्विस सुरंग के अंदर दुर्घटनाग्रस्त होने से कई बच्चों सहित 28 लोग मारे गए थे। गुरुवार को स्विट्जरलैंड में लगी आग नीदरलैंड के वोलेंडम नामक मछली पकड़ने वाले शहर में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर लगी भीषण आग के 25 साल बाद हुई है, जिसमें एक कैफे में जश्न मना रहे लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

नए साल की पूर्व संध्या पर यूनियनों द्वारा हड़ताल के आह्वान के बीच ज़ोमैटो और स्विगी ने गिग वर्कर्स को अधिक भुगतान की पेशकश की

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो और स्विगी अपने डिलीवरी पार्टनर्स को अधिक प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, जो त्योहारों के दौरान उनकी नियमित प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य गिग वर्कर्स यूनियनों द्वारा बुलाई गई हड़ताल के बीच नए साल की पूर्व संध्या पर सेवाओं में कम से कम व्यवधान सुनिश्चित करना है।

तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (टीजीपीडब्ल्यूयू) और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप–बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आईएफएटी) ने दावा किया है कि बेहतर वेतन और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर लाखों श्रमिक राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने वाले हैं। उद्योग सूत्रों के अनुसार, हड़ताल के कारण नए साल की पूर्व संध्या पर ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकइट, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो जैसी फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनियों के संचालन पर असर पड़ सकता है, जब मांग अपने चरम पर होती है।

ज़ोमैटो ने नए साल की पूर्व संध्या पर शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच व्यस्त समय में डिलीवरी पार्टनर्स को प्रति ऑर्डर 120 से 150 रुपये तक का भुगतान देने की पेशकश की है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि प्लेटफ़ॉर्म ने ऑर्डर की संख्या और कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर पूरे दिन में 3,000 रुपये तक की कमाई का भी वादा किया है।

इसके अलावा, ज़ोमैटो ने ऑर्डर अस्वीकार करने और रद्द करने पर लगने वाले जुर्माने को अस्थायी रूप से माफ कर दिया है, हालांकि उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह त्योहारों और साल के अंत के दौरान अधिक मांग वाले समय में अपनाई जाने वाली एक मानक परिचालन प्रक्रिया है। ज़ोमैटो और ब्लिंकइट ब्रांड की मालिक कंपनी एटर्नल के एक प्रवक्ता ने कहा, ष्यह त्योहारों के दौरान हमारी मानक वार्षिक परिचालन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें आमतौर पर बढ़ी हुई मांग के कारण कमाई के अधिक अवसर मिलते हैं।

इसी तरह, स्विगी ने भी साल के अंत के दौरान प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी है, जिसके तहत डिलीवरी कर्मचारियों को 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 10,000 रुपये तक की कमाई का मौका दिया जा रहा है। जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार , नए साल की पूर्व संध्या पर, प्लेटफॉर्म शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक छह घंटे की अवधि के लिए 2,000 रुपये तक की कमाई का विज्ञापन कर रहा है, ताकि साल के सबसे व्यस्त ऑर्डरिंग समय में पर्याप्त राइडर उपलब्ध रहें।

उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह के समय में बढ़ी हुई भुगतान राशि एक सामान्य प्रक्रिया है।

एक संयुक्त बयान में, ज्ळच्ँ और प्थ्।ज् ने कहा, "कल रात तक, भारत भर में 1.7 लाख से अधिक डिलीवरी और ऐप–आधारित श्रमिकों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है, और शाम तक यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।"

दूसरी ओर, जानकारों का कहना है कि 25 दिसंबर की व्यापक हड़ताल के बाद, जिसमें तेलंगाना और अन्य क्षेत्रों में हजारों डिलीवरी श्रमिकों ने प्लेटफॉर्म से लॉग ऑफ कर दिया था, गिग वर्कर्स ने 31 दिसंबर, 2025 को एक और बड़े पैमाने पर हड़ताल की घोषणा की है।

टीजीपीडब्ल्यूयू और आईएफएटी के संयुक्त बयान में कहा गया है,

"25 दिसंबर की कार्रवाई ने प्लेटफॉर्म कंपनियों को घटती कमाई, असुरक्षित डिलीवरी के दबाव और कार्यस्थल पर सम्मान की हानि के बारे में स्पष्ट चेतावनी दी थी।

हालांकि, कंपनियों ने चुप्पी साधे रखी – कम किए गए भुगतान को वापस नहीं लिया, श्रमिकों के साथ कोई बातचीत नहीं की और सुरक्षा या काम के घंटों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इस निरंतर उदासीनता ने आज की हड़ताल को अपरिहार्य बना दिया है।"

गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने भी भारत भर में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के अधिकारों, कल्याण और सम्मान से संबंधित मांगों को सामूहिक रूप से उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2025 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।

2025 की रिपोर्ट : जम्मू क्राइम ब्रांच ने 67 एफआईआर दर्ज कीं, जो पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक हैं

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू अपराध शाखा ने बुधवार को बताया कि उसने 2025 में गंभीर और जटिल आर्थिक अपराधों से संबंधित 67 एफआईआर दर्ज कीं और 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने इस उपलब्धि को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष जम्मू अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गंभीर और जटिल आर्थिक अपराधों से संबंधित रिकॉर्ड संख्या में मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया, 1,186 शिकायतों का समाधान किया और 67 नए मामले दर्ज किए, जो पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक हैं।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष एजेंसी द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल राशि 20 करोड़ रुपये रही। प्रवक्ता ने बताया कि ईओडब्ल्यू जम्मू की विभिन्न एफआईआर में शामिल कुल 22 आरोपियों को जम्मू और कश्मीर के भीतर और बाहर से विभिन्न टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया।

इन मामलों में गहन जांच, दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण और विभिन्न सरकारी विभागों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ निरंतर समन्वय की आवश्यकता थी। प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू शाखा ने कई भूमि धोखाधड़ी, हाई–प्रोफाइल मामले, प्रतिरूपण के मामले, धोखाधड़ी, वीजा धोखाधड़ी, सरकारी धन के दुरुपयोग और लोक सेवकों द्वारा आधिकारिक पद के दुरुपयोग की जांच की, जिसमें जम्मू जोन में संचालित अवैध नौकरी परामर्श कंपनियों पर विशेष ध्यान दिया गया।

उन्होंने कहा कि 2025 के दौरान, संगठित आर्थिक अपराधों में

जम्मू-कश्मीर आईटीआई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने उपमुख्यमंत्री से की मुलाकात, मांगों का ज्ञापन सौंपा

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू–कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जे–के आईटीआई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपमुख्यमंत्री श्री सुरिंदर कुमार चौधरी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष नज़ीर अहमद मोलवी ने किया। इस दौरान कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं और अपेक्षाओं को लेकर एक विस्तृत मांग पत्र उपमुख्यमंत्री को सौंपा गया। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि आईटीआई संस्थानों में कार्यरत बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्षों से अस्थायी, संविदा, अकादमिक कंसोलिडेटेड, गेस्ट फैकल्टी, सेल्फ फाइनेंस, आईएमसी और पीपीपी मोड पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इन सभी श्रेणियों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं के नियमित. ीकरण तथा वेतन में यथोचित वृद्धि की मांग प्रमुखता से उठाई। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि समान कार्य के बावजूद कर्मचारियों को समान वेतन और सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, जिससे उनके मनोबल और कार्यक्षमता पर असर पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने भर्ती नियमों के शीघ्र अंतिमकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि गजटेड और गैर–गजटेड पदों के लिए स्पष्ट और अद्यतन भर्ती नियमों के अभाव में विभागीय कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है और कर्मचारियों का करियर विकास भी बाधित हो रहा है। इसके साथ ही विभाग के पुनर्गठन और उन्नयन की मांग करते हुए संस्थान स्तर पर संरचनात्मक सुधार और पदों के युक्तिकरण की आवश्यकता बताई गई।

आईटीआई कर्मचारियों ने व्यावसायिक प्रशिक्षक और सामान्य प्रशिक्षक पदों के लिए एक समान पदनाम और नामकरण में बदलाव की भी मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि विभिन्न नामों और पदनामों के कारण न केवल भ्रम की स्थिति बनी रहती है, बल्कि इससे कर्मचारियों की पहचान और पदोन्नति से जुड़े मामलों में भी कठिनाइयां आती हैं। इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश जारी करने का आग्रह किया गया। बैठक में अन्य कई व्यावहा. रिक और प्रशासनिक मुद्दे भी उठाए गए।

इनमें पुस्तकालयाध्यक्ष और मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों में वेतन विसंगतियों को दूर करने, एमटीएस कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और कश्मीर डिवीजन के एमटीएस कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग शामिल थी। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इन मुद्दों के लंबे समय से लंबित रहने के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। इसके अलावा अकादमिक कंसोलिडेटेड और संविदा कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश, चिकित्सकीय अवकाश और एक स्पष्ट स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग भी रखी गई। कर्मचारियों का कहना था कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इन प्रावधानों के अभाव में विशेष रूप से महिला कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण के लिए नीलामी या कंडेमनेशन की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा करने और संस्थानों के प्रमुखों की उचित तैनाती सुनिश्चित करने की मांग भी की।

उपमुख्यमंत्री श्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की वास्तविक और जायज मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि आईटीआई कर्मचारी तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की रीढ़ हैं और उनके कल्याण से जुड़ी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उपमुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि लंबे समय से लंबित मामलों को चरणबद्ध तरीके से सुलझाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाएंगे।

बैठक के बाद जे–के आईटीआई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष नज़ीर अहमद मोलवी ने उपमुख्यमंत्री के सकारात्मक और आश्वस्त करने वाले रुख के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि संगठन को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही ठोस कदम उठाएगी और कर्मचारियों को राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक सभी मांगों का संतोषजनक समाधान नहीं हो जाता, तब तक संगठन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाता रहेगा।

इस मुलाकात को आईटीआई कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। कर्मचारियों को भरोसा है कि सरकार के आश्वासन के बाद उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस प्रगति होगी, जिससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि जम्मू–कश्मीर में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास प्रणाली भी और मजबूत हो सकेगी।

रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अंतिम हाई-स्पीड ट्रायल पूरा किया

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंतिम उच्च गति परीक्षण के सफल समापन के साथ भारतीय रेलवे ने आत्मनिर्भर रेल प्रौद्योगिकी की दिशा में अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा, रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) की देखरेख में आयोजित यह परीक्षण कोटा–नागदा खंड पर हुआ, जहां ट्रेन ने 180 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त की।ß हालांकि, इसके शुभारंभ की नई तिथि निर्दिष्ट नहीं की गई। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अतीत में कई बार लॉन्च की समय–सीमा चूक चुकी है। नवंबर के मध्य में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि यह ट्रेन दिसंबर 2025 में शुरू की जाएगी। वैष्णव ने 30 दिसंबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल ґ पर सुरक्षा परीक्षण का एक वीडियो साझा किया, जिसमें पानी से भरे गिलास की स्थिरता का प्रदर्शन दिखाया गया, जिसमें पानी से भरे गिलास उच्च गति पर भी बिना गिरे स्थिर रहे। "रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा आज वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परीक्षण किया गया, जो कोटा–नागदा खंड के बीच 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। हमारे अपने जल परीक्षण ने इस नई पीढ़ी की ट्रेन की तकनीकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया," वैष्णव ने पोस्ट में कहा। सुरक्षा परीक्षण के बारे में बात करते हुए, अधिकारियों ने कहा कि सवारी स्थिरता, दोलन, कंपन व्यवहार, ब्रेकिंग प्रदर्शन, आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम, सुरक्षा प्रणालियों और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों के आकलन सहित व्यापक तकनीकी मूल्यांकन किए गए। मंत्रालय के अधिकारियों ने एक प्रेस नोट में दावा किया, "ट्रेन का उच्च गति पर प्रदर्शन पूरी तरह से संतोषजनक पाया गया और रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा परीक्षण को सफल घोषित किया गया।" अधिकारियों के अनुसार, परीक्षण में इस्तेमाल की गई 16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्री यात्रा को ध्यान में रखकर बनाई गई है और अत्याधु. निक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है। "इनमें आरामदायक स्लीपर बर्थ, उन्नत सस्पेंशन सिस्टम, स्वचालित दरवाजे, आधु. निक शौचालय, अग्नि सुरक्षा और निगरानी प्रणाली, सीसीटीवी आधारित निगरानी, घ्डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली और ऊर्जा–कुशल तकनीकें शामिल हैं।

इन सुविधाओं का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करना है," उन्होंने आगे कहा। "सीआरएस हाई–स्पीड ट्रायल का सफल समापन एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है।

एसएस इनोवेशन्स इंटरनेशनल ने भारत की पहली रोबोटिक टेली-सर्जरी मैराथन की मेज़बानी की, एसएसआईएल मंत्रा के साथ 100 टेली-सर्जरी के ऐतिहासिक पड़ाव का जश्न

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली एसएसआईएल मंत्रा के डेवलपर, एसएस इनोवेशन्स इंटरनेशनल इंक. ने 100 रोबोटिक टेली–सर्जरी के सफल समापन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है। यह मील का पत्थर तकनीक–सक्षम स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह दर्शाता है कि उन्नत सर्जिकल विशेषज्ञता को स्वदेशी नवाचार के माध्यम से दूर–दराज़ क्षेत्रों तक भरोसेमंद ढंग से पहुँचाया जा सकता है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में, एसएस इनोवेशन्स इंटरनेशनल ने भारत की पहली मैराथन रोबोटिक टेली–सर्जरी का आयोजन किया, जिसके दौरान एक ही दिन में 20 से अधिक टेली–सक्षम रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक की गईं। यह पहल ᵓᵖ मंत्रा प्लेटफ़ॉर्म का वास्तविक क्लिनिकल प्रमाण प्रस्तुत करती है, जो विभिन्न सर्जिकल विशेषज्ञताओं में इसकी सटीकता, सुरक्षा और स्केलेबिलिटी को दर्शाती है। यह आयोजन स्वास्थ्य अवसंरचना को सशक्त बनाने और महानगरों से परे विशेषज्ञ–आधारित उपचार सेवाओं के विस्तार में रोबोटिक टेली–सर्जरी की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करता है।

यह उपलब्धि 1.4 अरब की आबादी वाले देश में टेली–सर्जरी की परिवर्तनकारी क्षमता को उजागर करती है, जहाँ उन्नत सर्जिकल देखभाल तक पहुँच अभी भी असमान है। दूरस्थ सर्जरी की सुविधा प्रदान कर, एसएसआईएल मंत्रा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अंतराल को पाटने, भौगोलिक असमानताओं को कम करने और एक अधिक समावेशी एवं सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण में योगदान देता है। साथ ही, यह चिकित्सा प्रौद्योगिकी और सर्जिकल नवाचार में भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका को भी सुदृढ़ करता है। डॉ. सुधीर श्रीवास्तव, संस्थापक, चेयरमैन एवं सीईओ, एसएस इनोवेशन्स इंटरनेशनल इंक., ने कहा, एसएसआईएल मंत्रा के साथ 100 टेली–सर्जरी पूरी करना भारतीय मेडटेक नवाच. ार के लिए एक निर्णायक क्षण है। यह मैराथन रोबोटिक टेली–सर्जरी बड़े पैमाने पर सटीकता और विश्वसनीयता का वास्तविक क्लिनिकल प्रदर्शन है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन्नत सर्जिकल देखभाल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित न रहे और भारत में विक. सित विश्वस्तरीय विशेषज्ञता सुरक्षित एवं भरोसेमंद तकनीक के माध्यम से हर मरीज तक पहुँच सके।" मैराथन रोबोटिक टेली–सर्जरी में विभिन्न विशेषज्ञताओं के अग्रणी सर्जनों ने भाग लिया। डॉ. सुधीर रावल, मेडिकल डायरेक्टर एवं प्रमुख – यूरो जेनिटो ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ने कहा, एसएसआईएल मंत्रा के माध्यम से रोबोटिक टेली–सर्जरी उन मरीजों के लिए सटीक और समयबद्ध कैंसर उपचार संभव बनाती है, जिन्हें विशेष सर्जिकल विशेषज्ञता तक पहुँच नहीं मिल पाती। यह मील का पत्थर ऑन्कोलॉजी देखभाल को बड़े पैमाने पर प्रदान करने के तरीके में एक सार्थक बदलाव को दर्शाता है।"

डॉ. मोहित भंडारी, प्रेसिडेंट, आईआरसीएडी इंडिया एवं डायरेक्टर दृ बैरिएट्रिक सर्जरी, मोहक बैरिएट्रिक्स एंड रोबोटिक्स, ने कहा,

"यह उपलब्धि टेली–सर्जरी को भविष्य की अवधारणा के बजाय एक व्यावहारिक और स्केलेबल समाधान के रूप में स्थापित करती है। यह दर्शाती है कि जटिल प्रक्रियाओं को भी क्लिनिकल परिणामों से समझौता किए बिना विकेंद्रीकृत किया जा सकता है।"

डॉ. चंद्रमोहन वड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं प्रमुख दृ यूरोलॉजी, प्रीति यूरोलॉजी एंड किडनी हॉस्पिटल्स, हैदराबाद, ने कहा,

"टेली–सर्जरी के दौरान एसएसआईएल मंत्रा प्रणाली की निरंतरता और त्वरित प्रतिक्रिया सर्जनों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और जटिल यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं के दायरे का विस्तार करती है।" डॉ. ललित मलिक, कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल, ने कहा, "हृदय शल्य चिकित्सा जैसी उच्च सटीकता वाली विशेषज्ञताओं में पूर्ण विश्वसनीयता अनिवार्य होती है।

ᵓᵖ मंत्रा का प्रदर्शन उन्नत दूरस्थ कार्डियक केयर के लिए इसकी मजबूती और बढ़ती प्रासंगिकता को दर्शाता है।"

डॉ. मगन मेहरोत्रा, सीनियर बैरिएट्रिक एवं रोबोटिक सर्जन, एपेक्स हॉस्पिटल, मुरादाबाद, ने कहा, "यह मैराथन रोबोटिक टेली–सर्जरी दर्शाती है कि स्वदेशी तकनीक किस प्रकार छोटे शहरों और वंचित क्षेत्रों में उन्नत सर्जिकल देखभाल को मरीजों के और करीब ला सकती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएँ न केवल सुलभ बल्कि किफायती भी बनती हैं।"

राजस्थान के टोंक में 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ दो गिरफ्तार

सबका जम्मू कश्मीर

टोंक : अधिकारियों ने बताया कि टोंक पुलिस की जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने बुधवार को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनकी कार से 150 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मोची के रूप में हुई है, दोनों बूंदी जिले के निवासी हैं। डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि सूचना के आधार पर, डीएसटी ने बरोनी पुलिस थाना क्षेत्र में एक कार को रोका और यूरिया उर्वरक की बोरियों में छिपाकर रखे गए लगभग 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया।

उन्होंने बताया कि आरोपी कथित तौर पर विस्फोटक सामग्री को बूंदी से टोंक में आपूर्ति के लिए ले जा रहे थे। अमोनियम नाइट्रेट के अलावा, पुलिस ने 200 कारतूस और लगभग 1,100 मीटर लंबे सेफ्टी फ्यूज तार के छह बंडल जब्त किए। सामग्री की ढुलाई के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त कर ली गई। मिश्रा ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानक. ारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई और जब्त विस्फोटक सामग्री के स्रोत, उपयोग और संभावित संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

उन्होंने आगे बताया कि पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगा रही है कि क्या यह खेप खनन सहित किसी भी अवैध गति. विधि के लिए थी।

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

वोट बैंक का लालच बना है पर्यावरण विनाश का कारण

प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड देश का सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। हर साल होने वाली प्राकृतिक आपदा भारी तबाही मचाती है। जिससे जानक् माल का भारी नुकसान होता है। इसका प्रमुख कारण है प्रकृति से छेड़छाड़। इसमें विकास के नाम पर वनों का विनाश और वन भूमि पर अतिक्रमण प्रमुख है।

योगेंद्र योगी

वोट बैंक का लालच सत्तारुढ़ दलों को इस कदर हाथ बांधे रखने के लिए मजबूर रखता है कि बेशक प्राकृतिक आपदाओं के विनाश से लोगों की जान ही क्यों न चली जाए। इसकी सरकारों को चिंताकृ परवाह नहीं है। लगता है उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया है हर हाल में वोट बैंक को बनाए रखना। ऐसी प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति तब सामने आई सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के प्रति जबरदस्त नारा. जगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में उत्तराखंड सरकार की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और उसके अधिकारी मूकदर्शक की तरह बैठे रहे और अदालत ने खुद मामले में संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। इस मामले में सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अवकाशक. ालीन पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक जांच समिति गठित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड देश का सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। हर साल होने वाली प्राकृतिक आपदा भारी तबाही मचाती है। जिससे जानकृमाल का भारी नुकसान होता है। इसका प्रमुख कारण है प्रकृति से छेड़छाड़। इसमें विकास के नाम पर वनों का विनाश और वन भूमि पर अतिक्रमण प्रमुख है। पिछले आठ वर्षों में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 3,554 लोगों की जान गई, 5,948 लोग घायल हुए और अरबों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ। मानस. ून का मौसम लगातार घातक साबित होता है, जिससे राज्य की पहले से ही नाजुक भूभाग पर हर साल एक नया घाव हो जाता है। बादल फटने से धारली में आई भीषण बाढ़ में 5,948 लोग घायल हुए और अरबों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ।

उत्तराखंड एक खतरनाक चक्र में फंस गया है। व्यापक और सक्रिय आपदा प्रबंधन के अभाव में, ष्देवभूमिष (देवताओं की भूमि) प्रकृति के प्रकोप से लगातार क्षतिग्रस्त होती रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि दशकों से हो रही देवदार के पेड़ों की कटाई ही उत्तरकाशी में बादल फटने की बढ़ती

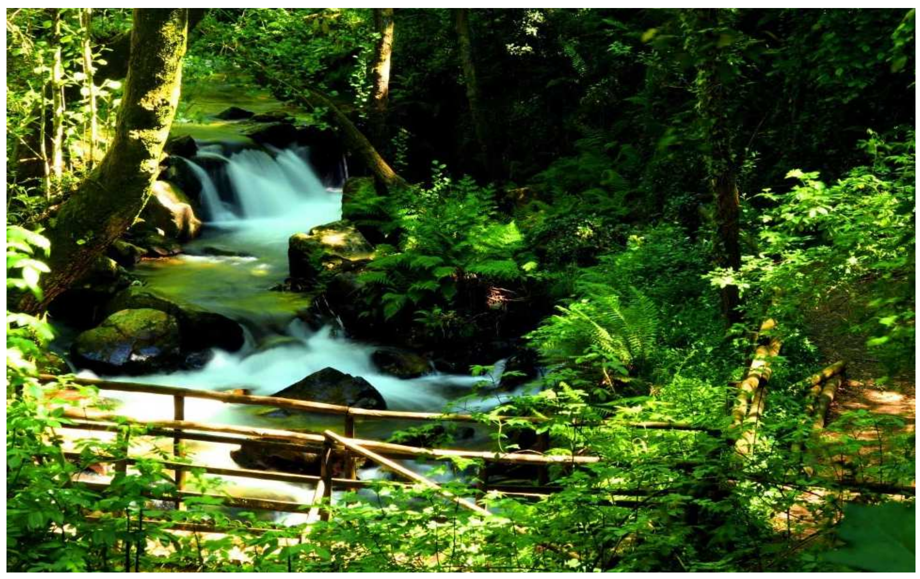

घटनाओं का मुख्य कारण है। देवदार के पेड़ों की जड़ें घनी होती हैं जो मिट्टी को बांधकर रखती हैं, कटाव को रोकती हैं और भारी बारिश या भूस्खलन के दौरान मलबे और पानी के बहाव को रोककर संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों की रक्षा करती हैं। वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि यदि धराली में ऐतिहासिक देवदार के वन क्षेत्र बरकरार रहते, तो इस आपदा का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता, या शायद नगण्य ही हो जाता।

एक समय उत्तराखंड के ऊंचे और हिमालयी क्षेत्र दृ विशेष रूप से समुद्र तल से 2,000 मीटर से ऊपर के इलाके दृ देवदार के घने जंगलों से आच्छादित थे। प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 400 से 500 देवदार के पेड़ पाए जाते थे। वन, जो प्राकृतिक ढलानों को स्थिर रखते हैं, उनकी कमी से जल निकासी बाधित होती है और पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर होता है, जिससे आपदाओं का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पेड़–पौधे मिट्टी को जकड़कर रखते हैं। जब पेड़ कटते हैं, तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है और भारी बारिश के दौरान आसानी से बह जाती है, जिससे भूस्खलन और मलबा प्रवाह होता है, जैसा कि 2013 के केदारनाथ आपदा में देखा गया था।

5 अगस्त, 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में आई विनाशकारी आपदा ने एक बार फिर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हिमालयी राज्य की दीर्घकालिक संवेदनशीलता को उजागर कर दिया था। इस त्रासदी में 66 लोग लापता हुए। पिछले एक दशक में राज्य में लगभग 18,464 प्राकृ तिक आपदाएँ दर्ज की गई, जिनसे भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड का इतिहास कई बड़ी आपदाओं से भरा पड़ा है। वर्ष 1991 के उत्तरक. ाशी भूकंप में 768 लोगों की जान गई, उसके बाद 1998 के मालपा भूस्खलन (225 मौतें) और 1999 के चमोली भूकंप (100 मौतें) का नंबर आता है। साल 2013 की केदारनाथ बाढ़ सबसे विनाशकारी रही, जिसमें 5,700 से अधिक लोगों की जान गई, जबकि 2021 की रेनी आपदा में मरने वालों की संख्या में 206 रही। पिछले एक दशक में दर्ज की गई 18,464 घटनाओं में से चौंका देने वाली 12,758 घटनाएं भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ के कारण हुईं।

भारत में 2024–2025 के आंकड़ों के अनुसार, 13,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा वन भूमि पर अतिक्रमण है, जो कि दिल्ली, सिक्किम और गोवा के कुल क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश और असम सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं, जहाँ लाखों हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में भी बड़ी मात्रा में वन भूमि अतिक्रमित है। जिससे वन, वन्यजीव और पर्यावरण को गंभीर खतरा है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा देश भर में वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जारी आंकड़ों के मुताबिक वन भूमि पर सर्वाधिक अतिक्रमण वाले राज्यों में मध्य प्रदेश और असम सबसे आगे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पर अवैध कब्जे हैं। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्य भी महत्वपूर्ण अतिक्रमण वाले राज्यों की सूची में शामिल हैं।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) को सौंपी एक रिपोर्ट में बताया था कि मार्च 2024 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 13,05,668.1 हेक्टेयर (या 13,056 वर्ग किमी) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अंतर्गत था।

इनमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर और दमन और दीव, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम मध्य प्रदेश, मिजा. ेरम और मणिपुर शामिल हैं।

इसके अलावा बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने वन अतिक्रमण से संबंधित आंकड़े और विवरण प्रस्तुत नहीं किए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की सरकारें पर्यावरण और वनों के विनाश को रोकने के लिए कितनी चिंतित हैं। यह मुद्दा राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल नहीं है। कारण साफ है इससे वोट नहीं मिलते, उल्टे वन भूमि पर अतिक्रमियों को हटाने से वोट बैंक का नुकसान होता है। यही वजह है कि सभी दल ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं। इसके बावजूद कि पर्यावरण बिगड़ने से होने वाली तबाही की कीमत देश को हर साल भारी जानकृमाल से चुकानी पड़ती है।

– योगेन्द्र योगी

योगेंद्र योगी हैं।)

जम्मू–कश्मीर की अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में मुकदमा चलाए गए तीन आरोपियों को बरी कर दिया

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर की एक सत्र अदालत ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में तीन लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

एनआईए अधिनियम के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

कुलगाम जिले के निवासी वाजिद अहमद भट, मसरत बिलाल भूरू और रमीज अहमद डार को सोमवार को बरी कर दिया गया। न्यायाधीश मनजीत राय ने निर्देश दिया कि यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है तो आरोपियों को तत्काल रिहा कर दिया जाए।

तीनों को 10 अक्टूबर, 2022 को शहर के बटमालू इलाके में एक चेकपोस्ट पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि उनके पास से ग्रेनेड और जिंदा कारतूसों वाली

मैगज़ीन बरामद हुई थीं।

अदालत ने कहा कि यह सर्वविदित है कि आपरा. धिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष को अपना मामला संदेह से परे साबित करना होता है और संदेह, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता। न्यायाधीश ने कहा, "इस मामले में आरो. पियों की गिरफ्तारी और उनसे बरामद सामान के संबंध में कई महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं।" उन्होंने कहा कि मामले की संपत्ति पर पहचान चिह्न या क्रमांक दर्ज करने और मुहरों को सुरक्षित रखने में सामूहिक विफलता रही, जिससे अभिरक्षा श्रृंखला टूट गई। उन्होंने कहा कि बम निरोधक दस्ते को ग्रेनेड की सील लगाने और प्रस्तुत करने के संबंध में विरोधाभासी साक्ष्य मौजूद हैं। न्यायालय ने गवाह. ें द्वारा आरोपियों की सही पहचान करने और विशिष्ट ग्रेनेड को विशिष्ट आरोपियों से जोड़ने में बार–बार असमर्थता और अल–बद्र से संबंध और आतंकवादी कृत्य के इरादे से संबंधित यूएपीए के आरोपों के लिए स्वतंत्र गवाह या सहायक साक्ष्य की पूर्ण अनुपस्थिति पर भी प्रकाश डाला। न्यायाधीश के आदेश में कहा गया, "एक बार ऐसा संदेह उत्पन्न होने पर, आरोपियों को संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायालय का मानना ध्है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी 10.10.2022 को कमांड पोस्ट बटमालू में कथित ग्रेनेड, मैगज़ीन और राउंड के सचेत और अनधिकृत कब्जे में थे, और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 के तहत आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।" आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मीर उर्फी, वहीद अहमद डार और अनिल रैना उपस्थित थे।

साप्ताहिक राशिफल

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपक. े निजी जीवन से लेकर करियर–कारोबार तक में उतार–चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। इस दौरान व्यक्तिगत और पेशेवेर रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज–मस्ती करते हुए बीतेगा। घर–परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्ताह के मध्य में आपको करियर–कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बदलाव को झेलना पड़ सकता है।

इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता रहेगी।

वृषभ

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। वृष राशि के जो जातक किसी कार्य विशेष के लिए बीते कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह भी उससे जुड़ी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले उनका पूर्वार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है।

ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने करियर–कारोबार और जीवन से जुड़े अहम कार्यों को इसी दौरान करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से मेल–मुलाकात होगी। जिसकी मदद से अटके कार्यों में धीमी गति से ही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में न सिर्फ कार्यक्षेत्र से जुड़ी बल्कि घर–परिवार से संबंधित समस्याएं भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी जमीन–जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। अचानक से जीवन में तमाम तरह की समस्याएं सामने आने से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके संगी–साथी आपकी ढाल बनेंगे और आपके साथ साए की तरह बने रहेंगे।

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो उम्मीद का दामन बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि इस सप्ताह उसमें आ रही बाधाएं स्वतरू दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है।

इस दौरान आपके शुभचिंतक आपको नेक सलाह देते हुए नजर आएंगे, जिस पर अमल करके आप अपनी चीजों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। इस पूरे सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक–कार्यों में खूब रमेगा। किसी धार्मिक–आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुक. ाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप समझदारी के साथ अपने पैसे का सही जगह निवेश करते हैं तो आपको उससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आएगा।

कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. ों को किसी भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। रिश्ते–नाते में मिठास बनी रहे और किसी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो इसके लिए स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार के सिलसिले में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलें। यदि कार्यक्षेत्र पर हालात आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप उससे बजाय भागने के उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। भूलकर भी आवेश में आकर नौकरी में बदलाव जैसा फैसला लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको आपके विरोधी आप पर हावी होने तथा आपके बनते काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. ों को अपनी ऊर्जा, धन और समय का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान कार्य विशेष के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर भी अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े बड़े फैसले इसी दौरान करने चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप कुछ चीजों को लेकर खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। नौकरीपेशा जातकों इस सप्ताह अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा पूर्व में की गई न सिर्फ आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट भी सुननी पड़ सकती है।

कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मनचाही सफलता और खुशियां मिले तो आपको अपने कार्य और व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा और अपने शुभचिंतकों को नाराज करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपकी किसी बात या व्यवहार से आपके अपने नाराज हो सकते हैं। वाद–विवाद बढ़ने पर वर्षों से बने रिश्ते में दरार आ सकती है। करियर–कारोबार से लेकर घर–परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहे इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करने करने की बजाय आपको खुद ही आगे बढ़कर प्रयास करना होगा।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में कनिष्ठ लोगों के साथ रुखा व्यवहार न करें और अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो शार्टकट तरीके से लाभ कमाने से बचें और कागजी काम पूरे करके रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन सावधानी के साथ करें।

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम और रिश्ते–नाते की दृष्टि से मध्यम फलदायी रहने वाला है।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह तुला राशि का नौकरीपेशा जातक हो या फिर व्यवसाय से जुड़ा कारोबारी, वह अपना शत प्रतिशत अपने कार्य में देता हुआ नजर आएगा।

खास बात कि उसके प्रयासों को सौभाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और सीनियर आपके कामकाज की खुले मन से प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत तक आपको बड़ा पद अथवा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी नये कारोबार की शुरुआत करने अथवा किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी–रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता–सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। करियर–कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यदि आपके कारोबार में बीते समय से कोई अड़चन आ रही थी इस सप्ताह वह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से दूर हो जाएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आप उसके विस्तार की योजना पर काम करेंगे। आपकी योजना को साकार रूप देने के लिए आपके शुभचिंतक और परिजन पूरी मदद करेंगे। इस संबंध में घर–परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लाभदायी साबित होगी। यह सप्ताह पठन–पाठन एवं शोध से जुड़े कार्यों को करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा।

धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन के नये अवसरों को लेकर आने वाला है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य और आशंका को त्याग कर कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस सप्ताह यदि आप अपने धन, समय और उर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आपको आशा से अधिक सफलता और लाभ मिल सकता हैं। वहीं इसकी अनदेखी करने पर बनते काम बिगड़ जाने से मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह खुले हाथ धन खर्च करने से बचना चाहिए अन्यथा सप्ताह के अंत तक उन्हें उधार मांगने की नौबत आ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है। परीक्षा–प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है।

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार–चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर–कारोबार में आ रही अड़चनों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र और कारोबार के अलावा निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपकी बड़ी चिंता का कारण बनेंगी। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन काफी मददगार साबित होंगे और काफी हद तक आप इन समस्याओं का समाधान खोजने में भी कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी भी कार्य को करते समय विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ बात–व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं अन्यथा लंबे समय से बने हुए रिश्तों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह खर्च की अधि. कता के चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर–कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है।

कुंभ

जीवन में आने वाली छोटी–मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। करियर और कारोबार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे और आपके पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है। सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल–मिलाप बढ़ेगा। आपके मान–सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने विरोधियों पर काबू पाने में कामयाब होंगे। कुंभ राशि के जो जातक तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक का कारोबार करने वालों को बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति से कार्य विशेष के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां अनुकूल तो वहीं उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों सप्ताह की शुरुआत में ही निबटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इसी दौरान पूरे मनोयोग से रोजी–रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से भूमि–भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ भी सकती है। ऐसे में अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी न करें और सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर में कोई धार्मिक अथवा मांग. लिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा–पाठ में बीतेगा।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

सीमा पार आतंकवाद पर कार्रवाई : पुंछ पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना की संपत्ति को यूएपीए के तहत जब्त किया

सबका जम्मू कश्मीर

पूंछ : सीमा पार आतंकवाद और उसके समर्थक नेटवर्कों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गैरकानूनी गति. विधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधानों के तहत पाकिस्तान स्थित एक आतंकी प्रवर्तक और लॉन्च कमांडर की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई पूंछ–राजौरी क्षेत्र में सक्रिय आतंकी संगठनों की वित्तीय और रसद संबंधी रीढ़ को ध्वस्त करने के जम्मू और कश्मीर पुलिस के दृढ़ संकल्प का संकेत है।

एक बयान में कहा गया है, ष्सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्कों के खिलाफ निर्णायक और दृढ़ कार्रवाई करते हुए, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधि. नियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत एक प्रति. बंधित आतंकी संगठन के पाकिस्तान स्थित आतंकी प्रवर्तक और लॉन्च कमांडर की अचल संपत्ति जब्त कर ली है।

यह कुर्की पुलिस स्टेशन गुरसाई, जिला पूंछ में दर्ज एफआईआर संख्या 194/2024 के संबंध में की गई है।

जब्त की गई संपत्ति में 4 मरला और 2 सरसाई कृषि भूमि शामिल है, जो गांव नर, नक्का मझरी क्षेत्र, तहसील मेंढर, जिला पूंछ में स्थित है।

बयान में कहा गया है कि जब्त की गई संपत्ति क्षेत्र के निवासी मोहम्मद अफसर के पुत्र रफीक नाई उर्फ घ्घ्सुल्तान की है, जो वर्तमान में प्रति. बंधित आतंकवादी संगठन तहरीक–उल–मुजा. हिदीन/जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के पाकिस्तान स्थित हैंडलर और लॉन्चिंग कमांडर के रूप में काम कर रहा है।

बयान में आगे कहा गया है कि आरोपी रफीक नाई उर्फ घ्घ्सुल्तान पुंछ–राजौरी सेक्टर में नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी की निगरानी, प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ में सहायता और आतंकवादी गतिविधियों को पुनर्जी. वित करने में सक्रिय रूप से शामिल है।

उसे ष्नामित व्यक्तिगत आतंकवादीष् घोषित किया गया है और वह कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैंरू एफआईआर संख्या 82/2003 धारा 302/307/120–बी/121/122/123 आरपीसी, 7/25/26/27 आईएए, पुलिस स्टेशन गुरसाई। एफआईआर संख्या 03/2004 धारा 302/307/120–बी/121/122 आरपीसी, 7/25/26/27 आईएए, थाना गुरसाई। एफआईआर संख्या 07/2006 धारा 302/364/120–बी आरपीसी, 7/25/26/27 आईएए, थाना गुरसाई। एफआईआर संख्या 14/2006 धारा 302/458/120–बी आरपीसी, 7/25/26/27 आईएए, थाना गुरसाई। एफआईआर संख्या 217/2020 धारा 121/122 आईपीसी, 18/20/23/38/39 यूएपीए, 7/25 एए, 4/5 ईएसए, पीएस मेंढर के तहत। एफआईआर संख्या 292/2020 धारा 120–बी/121/122 आईपीसी, 7/25/26/27 आईएए के तहत। 18/20/23/38 यूएपीए, पीएस मेंढर। एफआईआर संख्या 107/2021 धारा 302/307/120–बीआईपीसी, 7/25/ 26/27 आईएए, 15/18/20/23 यूएपीए, पीएस गुरसाई के तहत। एफआईआर संख्या 298/2022 धारा 18/23 यूएपीए, 120–बी/121/122 आईपीसी, 7/25 आईएए, थाना मेंढर। एफआईआर संख्या 94/2024 धारा 13/18/20/38 यूएपीए, थाना गुरसाई। कुर्की

मेंढर पुलिस स्टेशन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सभी कानूनी प्रक्रियाओं, सत्यापन, दस्तावेजीकरण और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की गई। कुर्क की गई संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग घ्10 लाख है।

यह कार्रवाई आतंकवादी नेटवर्कों के वित्तीय, रसद और सहायता ढांचे को नष्ट करने और राष्ट्र–विरोधी और आतंकवाद से संबंधित गति. विधियों में शामिल व्यक्तियों को उनके संसाधनों से वंचित करने की व्यापक और सतत रणनीति का हिस्सा है।

जिला पुलिस पुंछ आतंकवाद और राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक गति. विधियों में शामिल सभी तत्वों के खिलाफ दृढ़तापूर्वक और कानूनी रूप से कार्रवाई करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराती है और जनता को आश्वस्त करती है कि शांति, जन सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसे सभी उपाय जारी रहेंगे।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष कुंद्रा ने लद्दाख के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला

सबका जम्मू कश्मीर

लेह/जम्मू : रिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष कुंद्रा ने गुरुवार को लद्दाख के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला और केंद्र शासित प्रदेश में प्रभावी शासन, पारदर्शी प्रशासन और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

आधिकारिक बयान के अनुसार, एजीएमयूटी कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी कुंद्रा ने पवन कोटवाल का स्थान लिया, जो बुधवार को सेवानिवृत्त हुए थे।

पदभार ग्रहण करते हुए कुंद्रा ने प्रभावी शासन, पारदर्शी प्रशासन और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने, सेवा वितरण को बेहतर बनाने और विकास कार्यक्रमों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कुंद्रा ने कहा कि लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। बयान में

कहा गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासश् के दृष्टिकोण के अनुरूप, केंद्र शासित प्रदेश के सभी हिस्सों तक पहुंचने वाले सुलभ प्रशासन पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि प्रशासन को युवाओं की आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने और क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करने के लिए कमर कसनी होगी।

"लद्दाख का एक समृद्ध सभ्यतागत इतिहास है और यह हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है। इसे हमेशा संजोकर रखना और संरक्षित करना चाहिए," उन्होंने कहा।

कुंद्रा ने इस बात पर जोर दिया कि लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी को देखते हुए, विकास मॉडल में स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को शामिल करना अनिवार्य है, और इस क्षेत्र को विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण नहीं करना चाहिए।

Helpline

पुलिस स्टेशन	
बाग-ए-बहू	2459777
बख्शी नगर	2580102
बस स्टैंड	2575151
शहर	2543688
गांधी नगर	2430528
गंग्याल	2482019
नौबाद	2571332
पक्का डांगा	2548610
रेलवे स्टेशन	2472870
सैनिक कॉलोनी	2462212
सतवारी	2430364
चन्नी हिम्मत	2465164
ट्रांसपोर्ट नगर	2475444
त्रिकुटा नगर	2475133
गांधी नगर	2459660
एसएसपी शहर	2561578
एसपी शहर उत्तर	2547038
एसपी दक्षिण	2433778
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ	
इंडियन एयर लाइन्स	
शहर कार्यालय	2542735
एयर पोर्ट	2430449
जेट एयर वेज़	2453999
सिटी ऑफिस	2573399
रेलवे	
रेलवे पूछताछ	131, 132, 2476407
बुकिंग	2470318
आरक्षण	2470315
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्टेशन	
बख्शी नगर	2543557
गांधी नगर	2430786
कंपनी बाग	2542582
नया प्लॉट	2573429
पंजतीर्थी	2547537
दूरसंचार विभाग	
डायरेक्टरी पूछताछ	197
फॉल्ट रिपेयर	198
ट्रंक बुकिंग	180
बिलिंग शिकायत	2543896
जम्मू नगर पालिका	
जं. लाइन्स	2578503
प्रशासन अधिकारी	2542192
स्वास्थ्य अधिकारी	2547440
डाक सेवाएँ	
मुख्य डाकघर शहर	2543606
गाँधी नगर	2435863
अग्निशमन सेवाएँ	
नियंत्रण कक्ष	101,132, 2476407
शहर	2544263
गाँधी नगर	2457705
नहर	2554064
गंग्याल	2480026
रसोई गैस डीलर	
चिनाब गैस	2547633
गुलमौर गैस	2430835
जैकफेड	2548297
एचपी गैस	2578456
शिवांगी गैस	2577020
तवी गैस	2548455
पावर हाउस	
गाँधी नगर	2430180
नहर रोड	2554147
जानीपुर	2533828
नानक नगर	2430776
परेड	2542289
सतवारी कैंट	2452813
अस्पताल	
जीएमसी अस्पताल	2584290
एस.एम.जी.एस. अस्पताल	2547635
सी.डी. अस्पताल	2577064
डेंटल अस्पताल	2544670
गांधी नगर अस्पताल	2430041
सरवाल अस्पताल	2579402
जी.बी. पंत कैंट अस्पताल	2433500
आयुर्वेदिक कॉलेज	2543661
सी.आर.पी. अस्पताल	2591105
आचार्य श्री चंदर	2662536
मानसिक अस्पताल	2577444
स्वामी विवेकानंद	2547418
ब्लड बैंक	2547637
एम्बुलेंस	2584225, 2575364
एम्बुलेंस (रेड क्रॉस)	2543739
नर्सिंग होम	
मददन अस्पताल	2456727
मेडिकेयर	2435070
त्रिवेणी नर्सिंग होम	2452664
सुविधा नर्सिंग होम	2555965
अल. फिरदौस नर्सिंग होम	2545050
आस्था नर्सिंग होम	2576707
बी एन चौरिटेबल ट्रस्ट	2505310
चोपड़ा नर्सिंग होम	2573580
हरबंस सिंह मेम हॉस्पिटल	2541952
जीवन ज्योति	2576985
युद्धवीर नर्सिंग होम	2547821
मीडियाएड नर्सिंग होम	2466744
सीता नर्सिंग होम	2435007
विभूति नर्सिंग होम	2547969
रामेश्वर नर्सिंग होम	2580601
बी एन चेरिटेबल	2555631
महर्षि दयानंद	2545225

श्रम कोड और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जागरूकता शिविर आयोजित

सबका जम्मू कश्मीर

राजौरी : श्रम विभाग जिला राजौरी ने बुधवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई राजौरी के परिसर में श्रम कोड और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर एक जागरूकता एवं संवादात्मक शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हाल ही में लागू किए गए चार नए श्रम कोडों तथा उनके श्रमिकों नियोक्ताओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों की जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम का आयोजन सहायक श्रम आयुक्त राजौरी प्रद्योत गुप्ता के मार्गदर्शन में किया गया। इसमें श्रमिकों विभिन्न प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों तथा जिला न्यायालय राजौरी के अधिवक्ताओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य हालिया श्रम सुधारों की जानकारी देना था जिनमें मजदूरी संहिता 2019 औद्योगिक संबंध संहिता 2020 सामा. जिक सुरक्षा संहिता 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता 2020 शामिल हैं। इस अवसर पर आईटीआई राजौरी के प्रधानाचार्य उज्ज्वल महाजन व्यापार मंडल राजौरी के उपाध्यक्ष ताहिर सज्जाद लोन अधिवक्ता आफताब आलम अधिवक्ता अरफान अहमद चौधरी अधिवक्ता शजाहित अहमद जमील तथा श्रम अधिकारी नीरज कुमार ने कार्यक्रम में भाग लिया और अपने विचार रखे।

सहायक श्रम आयुक्त प्रद्योत गुप्ता ने अपने संबोधन में बताया कि नए श्रम कोड औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं ताकि नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित हो सकें।

उन्होंने कहा कि ये संहिताएं श्रमिकों को निवारक सुलहात्मक न्यायिक और दंडात्मक प्रावधानों के माध्यम से वैधानिक सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा श्रमिक वर्ग की कठिनाइयों को कम करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों को भी प्रोत्साहित करती हैं।

श्रम अधिकारी नीरज कुमार ने भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में भी अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने श्रम कोडों से संबंधित विषयों पर सक्रिय रूप से संवाद किया जिससे कार्यक्रम जानकारीपूर्ण और प्रभावी रहा। हितधारकों की मौके पर ही शिकायतों का समाधान किया गया जिससे बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और सामा. जिक सुरक्षा कवरेज को मजबूत करने में सहायता मिली।

एयर मार्शल नागेश कपूर ने वायु सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : एयर मार्शल नागेश कपूर ने गुरुवार को भारतीय वायु सेना के उप वायु सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला।

इस नियुक्ति से पहले, वे दक्षिण पश्चिमी वायु कमान (एसडब्ल्यूएसी) के वायु अधिकारी कमान–इन–चीफ के पद पर कार्यरत थे।

वह एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लेंगे, जो राष्ट्र की चार दशकों की शानदार सेवा के बाद बुधवार को सेवानिवृत्त हुए।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने एक पोस्ट में बताया, "एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायु सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया।

दिसंबर 1986 में आईएएफ की फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन प्राप्त करने वाले नागेश कपूर को आईएएफ के विभिन्न लड़ाकू और प्रशिक्षण विमानों को उड़ाने का व्यापक अनुभव है।"

उन्होंने वायु भवन में उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला।

एयर मार्शल कपूर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

एसएसपी सांबा ने प्रेस वार्ता कर वर्ष 2025 की उपलब्धियां गिनाई

सबका जम्मू कश्मीर

सांबा : सांबा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वर्ष 2025 के दौरान सांबा पुलिस की प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पुलिस जन सहभागिता को मजबूत करने की दिशा में सांबा पुलिस ने उल्लेखनीय कार्य किया है।

प्रेस वार्ता में एसएसपी सांबा ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान की विस्तार से जानकारी दी। वर्ष 2025 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 70 एफआईआर दर्ज की गईं जो वर्ष 2024 की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक हैं। चालू व पूर्व वर्षों के मामलों की निस्तारण दर 81.55 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। पिट एनडीपीएस अधिनियम के तहत चार मादक पदार्थ तस्करों को निरुद्ध किया गया जो 100 प्रतिशत की वृद्धि है। नशा तस्करों की संपत्तियों की कुर्की में 33 प्रतिशत तथा कुर्क संपत्तियों के मूल्य में 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एनडीपीएस मामलों में आगे और पीछे की कड़ियों में भी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। चिन्हित ड्रग हॉटस्पॉट्स पर केंद्रित कार्रवाई से एफआईआर में 111 प्रतिशत गिरफ्तारियों में 84 प्रतिशत वाहन जब्ती में 146 प्रतिशत तथा आवारा व्यक्तियों की हिरासत में 127 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त नशा विरोधी जागरूकता और युवाओं की भागीदारी के तहत वाद विवाद प्रतियोगिताएं खेलकूद कार्यक्रम पीसीपीजी बैठकें थाना दिवस कार्यक्रम तथा विद्यार्थियों के लिए भारत दर्शन टूर आयोजित किए गए।

सामान्य अपराध के मामलों में निस्तारण दर पिछले वर्ष के 52 प्रतिशत से बढ़कर चालू वर्ष में 55.54 प्रतिशत हो गई।

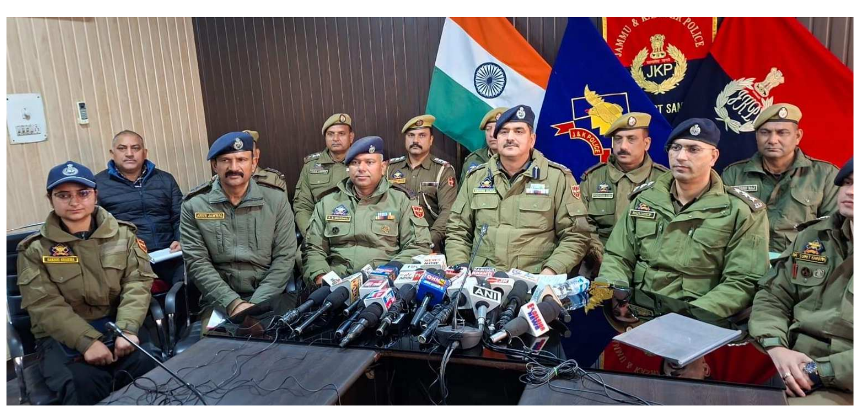

अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई के तहत वर्ष 2025 में 652 वाहनों को जब्त किया गया जो 2024 की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक है। अवैध खनन में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ जिले भर में मामले दर्ज किए गए।

गो तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई में 85 मामले दर्ज किए गए 75 वाहन जब्त किए गए 703 पशुओं को मुक्त कराया गया तथा 83 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए नियमित गश्त 24×7 डायल 112 हेल्पलाइन का प्रभावी उपयोग सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम तथा एफआईआर का त्वरित पंजीकरण एवं निस्तारण सुनिश्चित किया गया। महिला सेल सांबा एवं सभी पांच थानों में महिला सहायता डेस्क 24 घंटे महिला स्टाफ के साथ कार्यरत रहे।

लापता व्यक्तियों के मामलों में 110 व्यक्तियों को तलाश कर उनके परिजनों से मिलाया गया।

फरार आरोपियों में से 19 को गिरफ्तार किया गया। निवारक कार्रवाई के तहत 989 व्यक्तियों के विरुद्ध 525 निवारक कदम उठाए गए।

ऑपरेशन सिंदूर एवं फ्लैश फ्लड्स के दौरान त्वरित कार्रवाई व राहत के अंतर्गत सीमा क्षेत्र के गांवों से 8165 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया जबकि फ्लैश फ्लड्स के दौरान 465 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया।

साइबर अपराध के मामलों में वर्ष 2025 के दौरान 32,79,293 रुपये की राशि पीड़ितों को रिफंड कराई गई जबकि 70,87,831 रुपये की राशि को लियन के रूप में सुरक्षित किया गया। इसके अलावा जिले भर में शैक्षणिक संस्थानों कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर 59 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

यातायात नियम उल्लंघन के विरुद्ध 1283 चालान किए गए जो पिछले वर्ष की तुलना में 94 प्रतिशत अधिक हैं।

एसएसपी सांबा ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी प्रकाश डाला जिनके तहत जीरो एफआईआर एवं ई एफआईआर का उपयोग किया गया। संगठित अपराध के मामले दर्ज किए गए तथा अनुपस्थिति में मुकदमा और सामुदायिक सेवा जैसे दंड प्रावधानों को लागू किया गया। अंत में एसएसपी सांबा ने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों के समर्पण और मेहनत की सराहना करते हुए आम जनता व मीडिया के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और जिले में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पेश. `वर पारदर्शी व जवाबदेह कार्यप्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।

तंबाकू पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर 1 फरवरी से प्रभावी होगा

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर नया उपकर लागू करने की तिथि अधिसूचित की।

तंबाकू और पान मसाला पर ये नए शुल्क जीएसटी दर के अतिरिक्त होंगे और वर्तमान में इन पर लगने वाले क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार

, 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा।

इसके अतिरिक्त, पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर भी लगेगा, जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू होगा।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबा. कू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण एवं शुल्क संग्रह) नियम, 2026 को अधिसूचित किया।

संसद ने दिसंबर में दो विधेयकों को मंजूरी दी थी, जिनमें पान मसाला निर्माण पर नया स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर तथा तंबाकू पर उत्पाद शुल्क लगाने की अनुमति दी गई थी।

सरकार ने बुधवार को इन शुल्कों के लागू होने की तिथि 1 फरवरी निर्धारित की। वर्तमान में अलग–अलग दरों पर लगाया जाने वाला जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर 1 फरवरी से समाप्त हो जाएगा।

एम्स-जम्मू ने ट्रॉमेटोलॉजी संस्थान और स्वास्थ्य सेवा में एआई के लिए केंद्र प्रस्तावित किया है

सबका जम्मू कश्मीर

सांबा : अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एआईएमएस), जम्मू ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें इज़राइल और यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख संस्थानों के सहयोग से ट्रॉमेटोलॉजी संस्थान और स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है।

अधिकारियों ने बताया कि एआईएमएस नए साल में नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा और ओपन हार्ट सर्जरी सहित कई नई सुविधाएं शुरू करेगा।

एआईएमएस–जम्मू के कार्यकारी निदेशक और सीईओ, प्रोफेसर शक्ति कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित ट्रॉमेटोलॉजी संस्थान देश में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सचिवालय सेवा के अधिकारियों के तबादलों का आदेश दिया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : म्मू और कश्मीर सरकार ने प्रशासन के हित में तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर सचिवालय (अधीनस्थ) सेवा के चार अधिकारियों के तबादलों और तैनाती के आदेश दिए हैं।

सरकारी आदेश संख्या 1978-जेके (जीएडी) दिनांक 2025 के अनुसार, प्रभारी अनुभाग अधिकारी श्री नजीर अहमद पम्पोरी का तबादला जम्मू-कश्मीर के अभियोजन निदेशालय से आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग में कर दिया गया है।

प्रधान सहायक श्री निशांत देव का तबादला संपदा विभाग से जम्मू स्थित जम्मू के विशेष न्यायाधिकरण में कर दिया गया है, जबकि प्रधान सहायक श्री शहजादा लायकत खान को आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग से जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग में स्थानांतरित कर दिया गया है।

इसी प्रकार, प्रधान सहायक श्री कश्मीरी लाल का तबादला उच्च शिक्षा विभाग से कर संपदा विभाग में कर दिया गया है।

आदेश में आगे कहा गया है कि सभी अधिकारियों को कार्यभार से मुक्त मान लिया जाएगा। ये तबादले जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आयुक्त/सचिव एम. राजू (आईएएस) के हस्ताक्षर से किए गए हैं।

सलमान खान जैसे हैं वैसे ही हैं, उनमें जरा भी दिखावा नहीं है : बैटल ऑफ गलवान के सह-कलाकार के बारे में चित्रांगदा सिंह का विचार

सबका जम्मू कश्मीर

मुंबई : अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह, जो फिल्म ष्बैटल ऑफ गलवानष् में सलमान खान के साथ नजर आने वाली हैं, का कहना है कि सुपरस्टार बिना किसी झिझक के अपने असली रूप में हैं, जो एक ऐसे उद्योग में दुर्लभ है जहां ष्कई लोग मुखौटा पहनते हैंष्।

"शूटआउट एट लोखंडवाला" के निर्देशक अपूर्वा लखिया द्वारा निर्देशित, यह बहुप्रतीक्षित युद्ध ड्रामा भारत और चीन के बीच 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है।

"वह अपने प्रशंसकों की चाहतों को बखूबी समझते हैं और ठीक वैसे ही हैं जैसे उनके प्रशंसक उन्हें पसंद करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह कुछ और होने का दिखावा करते हैं। उनके बारे में सबसे अद्भुत बात यह है कि उनमें जरा भी बनावटीपन नहीं है३ मैंने इंडस्ट्री में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो बिल्कुल बनावटी हो, वह यही हैं। वह जैसे हैं वैसे ही हैं। जब उनका मन करेगा तब बोलेंगे, जब तक उनका मन करेगा तब तक चुप रहेंगे, अगर उन्हें अभी कसरत करनी है तो वे जाकर कसरत करेंगे," सिंह ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में बताया।

वह खान की इस बात के लिए प्रशंसा करती थीं कि वह ष्जैसे हैं वैसे ही हैं और कुछ और बनना नहीं चाहतेष्।

"यह अजीब है क्योंकि इस इंडस्ट्री में, कभी-कभी आप प्रभाव डालने के लिए चीजें करते हैं। मैंने उनमें एक बात की प्रशंसा की है, शायद यही। ऐसा करना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि उनके प्रशंसक उन्हें इसी वजह से पसंद करते हैं क्योंकि वह बहुत ही वास्तविक हैं," अभिनेता ने आगे कहा।

फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में विवरण दिए बिना, सिंह ने खान की सहज अभिनय शैली की प्रशंसा की।

"वह इतना आत्मविश्वासी है कि आप उससे कुछ भी कह सकते हैं और उसे बिना तैयारी के बोलना बहुत पसंद है। यही सबसे अच्छी बात है।

यह एक निरंतर विकसित होने वाले दृश्य की तरह है जब तक कि अंत में सब ठीक न हो जाए। तब तक, यह बस विकसित होता रहता है, मुझे यह बहुत पसंद है।

दिसंबर 2025 में जीएसटी संग्रह में 6 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 1.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, व्यापक कर कटौती के बाद घरेलू बिक्री से राजस्व में धीमी वृद्धि के चलते दिसंबर 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 6.1 प्रतिशत बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। दिसंबर 2024 में

सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक था।

घरेलू लेनदेन से सकल राजस्व 1.2 प्रतिशत बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व दिसंबर 2025 में 19.7 प्रतिशत बढ़कर 51,977 करोड़ रुपये हो गया।

दिसंबर में धनवापसी 31 प्रतिशत बढ़कर 28,980 करोड़ रुपये हो गई।

रिफंड को समायोजित करने के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.2 प्रतिशत अधिक है।

पिछले महीने उपकर संग्रह घटकर 4,238 करोड़ रुपये रह गया, जबकि दिसंबर 2024 में यह 12,003 करोड़ रुपये था।

22 सितंबर, 2025 से लगभग 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम कर दी गई हैं, जिससे सामान सस्ता हो गया है।

नववर्ष 2026 पर पवन शर्मा ने दी शुभकामनाएं, विक्रम संवत को आधिकारिक मान्यता देने की उठाई मांग

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : पवन शर्मा, राज्य सचिव, भारतीय जनता पार्टी, जम्मू और कश्मीर ने आज कैलेंडर के नए साल 2026 के मौके पर देश के लोगों को दिल से बधाई दी। उन्होंने आने वाले साल में सभी के अच्छे स्वास्थ्य, शांति, खुशहाली और सामूहिक तरक्की की कामना की।

अपने संदेश में, पवन शर्मा ने कहा कि हालांकि कैलेंडर के हिसाब से नया साल दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, अब समय आ गया है कि भारत विक्रम संवत के अनुसार भारतीय नववर्ष को आधिकारिक तौर पर घोषित करके अपनी सभ्यता की चेतना को फिर से पक्का करे। संवत कैलेंडर, जो भारत के पुराने, साइंटिफिक और समय पर परखे हुए क्रोनोलॉजी सिस्टम पर आधारित है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि विक्रम संवत सिर्फ़ एक पारंपरिक कैलेंडर नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक रूप से विकसित एक फ्रेमवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी, मैथ और प्राकृतिक चक्रों के बारे में भारत के गहरे ज्ञान को दिखाता है। इस कैलेंडर के अनुसार भारतीय नए साल को पहचानना भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक निरंतरता और समृद्ध बौद्धिक विरासत का सम्मान करने की दिशा में एक सार्थक कदम होगा। पवन शर्मा ने कहा कि इस तरह की पहल से न सिर्फ़ देश का गर्व और कल्चरल सेल्फ़-अवेयरनेस मज़बूत होगी, बल्कि भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक सिविलाइज़ेशनल लीडर के तौर पर भी जगह मिलेगीकृजो अपने पुराने ज्ञान का सम्मान करता है और पूरे भरोसे के साथ अपने भविष्य को बनाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की हमेशा से चली आ रही परंपरा में देसी ज्ञान सिस्टम और सस्टेनेबल सिविलाइज़ेशनल प्रैक्टिस पर ग्लोबल बातचीत में अहम योगदान देने की क्षमता है।

इस अवसर पर पवन शर्मा ने केंद्र सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र उन्होंने मोदी से इस दिशा में सार्थक और निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत लगातार अपनी सांस्कृतिक जड़ों को वापस पा रहा है और उन्हें दुनिया के सामने गर्व और स्पष्टता के साथ पेश कर रहा है।

विक्रम संवत के अनुसार भारतीय नववर्ष की आधिकारिक घोषणा संवत भारत की आत्मा को मज़बूत करेगा, इसकी खास पहचान को मज़बूत करेगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाकर रखेगा। पवन शर्मा ने यह भी कहा कि सरकारी और पब्लिक ज़िंदगी में इंग्लिश कैलेंडर का लगातार दबदबा, कॉलोनियल अतीत की विरासत है, और भारत के अपने कैलेंडर सिस्टम की ओर सोच-समझकर बदलाव, एक कॉन्फिडेंट, मॉडर्न भारत में सच्ची इंटेलेक्चुअल आज़ादी और कल्चरल सेल्फ़-रिस्पेक्ट की निशानी होगी।

अपनी बात खत्म करते हुए, पवन शर्मा ने एक बार फिर सभी नागरिकों को नए साल की शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि साल 2026 भारत के कल्चरल रेनेसां, नेशनल यूनिटी और एक डेवलप्ड देश के विज़न की तरफ़ सफ़र में नए माइलस्टोन तय करेगा।

नए साल की रात रणथंभौर में गांधी-वाड्रा परिवार, कड़ी सुरक्षा के बीच रेहान की रिंग सेरेमनी की अटकलें

नई दिल्ली

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान की सगाई को लेकर इन दिनों गांधी वाड्रा परिवार देश में सुर्खियों बना हुआ है. इसी को लेकर राजस्थान में सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर के होटल शेरबाग में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का परिवार ठहरा हुआ है. गांधी वाड्रा परिवार के होटल शेरबाग में ठहरने को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. साथ ही सवाई माधोपुर जिला प्रशासन और पुलिस की भी होटल शेरबाग के चप्पे-चप्पे पर तैनाती है. यहां तक की होटल के रास्ते पर भी किसी को भटकने की इजाजत नहीं है.

परिवार की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है.

अभी आगामी दो दिन तक गांधी वाड्रा परिवार के रणथंभौर में ठहरने की खबर है.

आज 31 दिसंबर की रात्रि को नए साल का जश्न गांधी परिवार होटल में ही मानने वाला है. इसके साथ ही बताया जा रहा है कि होटल के मालिक जैसल सिंह के जुड़वा पुत्र और पुत्री का जन्म दिवस भी आज है. रात में बर्थडे सेलिब्रेशन होगा. साथ ही बताया जा रहा है कि बेहद अनौपचारिक रूप से रेहान और अवीवा बेग की रिंग सेरेमनी की एक औपचारिक रश्म भी निभाई जा सकती है. जो कि नए साल के अवसर पर रणथंभौर भ्रमण के लम्हों को यादगार बनाएगी.

हालांकि गांधी परिवार का कोई सदस्य या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी गांधी परिवार के कार्यक्रमों की किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है.

जैसल सिंह के कहने पर पहुंचा गांधी-वाड्रा परिवार। परिवार का दौरा पूरी तरह से बेहद निजी है. इसको देखते हुए ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है.

एन डी एस ने सुनैना कैला का भक्ति भजन 'रज्ज रज्ज दर्शन' किया रिलीज़

डोगरी भाषा और भक्ति संगीत को बढ़ावा देने की दिशा में नामी डोगरी संस्था की पहल

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू। नामी डोगरी संस्था ने जम्मू–कश्मीर की उभरती गायिका सुनैना कैला द्वारा लिखे और गाए गए भक्ति ऑडियो–वीडियो भेंट 'रज्ज रज्ज दर्शन' को औपचारिक रूप से रिलीज़ किया। यह भक्ति गीत 'माँ बाबे आली' को समर्पित एक श्रद्धांजलि है। गाने का निर्माण विशाल आनंद ने श्रज्ञ टॉप प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है, जबकि इसका संगीत विक्रम शर्मा ने तैयार किया है।

भजन रिलीज़ कार्यक्रम में जम्मू–कश्मीर की मशहूर गायिका और एन डी एस की मुख्य संरक्षक प्रो. अनुपमा शर्मा,

एन डी एस अध्यक्ष डोगरा हरीश कैला, महासचिव यश पाल यश, कार्यकारी सदस्य सुशील भोला, प्रसिद्ध डोगरी लेखक नरेंद्र सिंह चिब, जाने–माने भक्ति गीत गायक सुरेश पूंछी और जानी–मानी गायिका, डोगरी कवयित्री व रेडियो उद्घोषक डॉ. चंचल शर्मा मौजूद रहे।

इस अवसर पर सुनैना कैला के माता–पिता भरत भूषण कैला और सीमा कैला भी उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रो. अनुपमा शर्मा ने कहा कि डुग्गर भूमि को शक्ति, शिव, विष्णु और स्थानीय देवताओं की दिव्यता का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने प्रोडक्शन एजेंसियों से आग्रह किया कि वे अच्छी गुणवत्ता के संगीत के माध्यम से डुग्गर की भक्ति परंपरा को और अधिक उजागर करें। एन डी एस अध्यक्ष हरीश कैला ने कहा कि संगीत अच्छी कविता को जन–जन तक पहुंचाने और डोगरी भाषा को लो. कप्रिय बनाने का सशक्त माध्यम है और एन डी एस इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। महासचिव यश पाल यश ने कहा कि डोगरी भक्ति साहित्य और संगीत के क्षेत्र में कलाकारों के लिए अपार संभावनाएं हैं। वहीं नरेंद्र सिंह चिब ने डोगरी भाषा में सुनैना कैला के प्रयासों की सराहना की। सुरेश पूंछी ने पूरी टीम को इस सफल भक्ति प्रस्तुति के लिए बधाई दी।

कार्यक्रम की वीडियोग्राफी मशहूर गिटारवादक और डॉक्यूमेंट्री निर्माता शिवेंद्र कुमार ने की। कार्यक्रम का संचालन यश पाल यश ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सुशील भोला ने प्रस्तुत।

भाजपा ने मोदी को धन्यवाद दिया सरकार ने 1,430 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता के लिए आवेदन किया

आपदा राहत फंड के किसी भी गलत इस्तेमाल के खिलाफ एनसी सरकार को चेतावनी दी

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक शाम लाल शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और विधायक डॉ. नरिंदर सिंह, विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया , डॉ. देविंदर कुमार मन्याल , चौ. विक्रम के साथ रंधावा , अरविंद गुप्ता और भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ. प्रदीप महोत्रा ने जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

मीडिया से बात करते हुए शाम लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से शुक्रिया अदा किया। मोदी और केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए घ1,430 करोड़ के स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस पैकेज को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद दिया , ताकि 24 अगस्त को जम्मू इलाके में आई भयानक बाढ़ और लगातार बारिश से खराब हुए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा सके। शाम लाल शर्मा ने कहा कि इस आपदा ने जम्मू, सांबा, रियासी , किश्तवाड़ और दूसरे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, जिससे सड़कों, पुलों, पानी की सप्लाई सिस्टम, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ फैसिलिटी और दूसरे ज़रूरी पब्लिक एसेट्स को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि आपदा के तुरंत बाद, ठश्रच ने नुकसान का पूरा असेसमेंट करने के लिए सीनियर लीडरशिप से लेकर ग्राउंड–लेवल वर्कर्स तक की टीमें बनाईं। इसके आधार पर, एक डिटेल्ड और सही नुकसान की रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को सौंपी गई। इसके बाद, केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, स्ळ और सीनियर अधिकारियों के साथ हाई–लेवल मीटिंग कीं, और ठश्रच डस्| ने उन्हें लोगों को हुए नुकसान की गंभीरता से खुद अवगत कराया। शाम लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी के नेतृत्व में, राहत को तेज़ी से पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की अगुवाई में सीनियर केंद्रीय मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी। श्र–ज्ञ ठश्रच के 4 डच और 7 डस्| वाले एक डेलीगेशन ने नई दिल्ली में ठश्रच के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और केंद्रीय वित्त मंत्री समेत केंद्रीय लीडरशिप से मुलाकात की, जिसके बाद घ1,430 करोड़ के स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस पैकेज को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि यह मदद रेगुलर यूनियन बजट और डिज़ास्टर रूटीन फंड से अलग है, और यह रिकवरी और डिज़ास्टर मिटिगेशन के लिए एक टारगेटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। मंजूर की गई रकम में से, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत पहली किस्त के तौर पर घ944 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं । अब तक, असल प्रोजेक्ट एग्ज़िक्यूशन पर घ758 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। इस्तेमाल पक्का करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट रोज़ाना निगरानी के साथ पूरे प्रोसेस पर सेंट्रली नज़र रख रहा है । लाल शर्मा ने कड़ी और साफ़ चेतावनी देते हुए छब की सरकार को जम्मू के आपदा प्रभावित इलाकों के लिए खास तौर पर रखे गए इन फंड का गलत इस्तेमाल करने , उन्हें दूसरी जगह लगाने या फिर से बांटने की किसी भी कोशिश के खिलाफ आगाह किया।

उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले,"क्त्थ के तहत जारी 209 करोड़ रुपये में से छब सरकार ने मनमाने ढंग से सभी जिलों को 10–10 करोड़ रुपये बांट दिए , जिसमें आपदा से अप्रभावित जिले भी शामिल थे, और जम्मू क्षेत्र के बुरी तरह प्रभावित जिलों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया। उन्होंने इसे जम्मू के सबसे ज़्यादा प्रभावित आपदा प्रभावित इलाकों, जैसे जम्मू, सांबा, कठुआ , उधमपुर , किश्तवाड़ (चसोती), रामबन , रियासी और राजौरी के कुछ हिस्सों, खासकर कालाकोट–सुंदरबनी– नौशेरा , के साथ बहुत बड़ी हेराफेरी, एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी और भेदभाव वाला व्यवहार बताया। शाम लाल शर्मा ने इस नाइंसाफ़ी के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को ज़िम्मेदार ठहराया, जिनके पास फ़ाइनेंस और राहत और पुनर्वास विभाग भी हैं, और चेतावनी दी कि ठश्रच ऐसी किसी भी गड़बड़ी को दोबारा बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा, "इस 1,430 करोड़ रुपये का हर रुपया जम्मू के आपदा प्रभावित लोगों का है। बीजेपी यह पक्का करेगी कि इसे समझदारी से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और तय तरीके से ही खर्च किया जाए। छब सरकार की इस फंड को दूसरी जगह लगाने की किसी भी कोशिश का हर लेवल पर कड़ा विरोध किया जाएगा, उसे सामने लाया जाएगा और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।"

लोहड़ी पर विशेष

निर्धन बेटी पदवी पाए तो कहलाए लोहड़ी।
उदय सूरज की पगडंडी लेकर आए लोहड़ी।
सुख स्मृति आनंद अवस्था शुभ संकल्प बने।
वास्तविक निर्मित पुरुषार्थ के बादल हों घने।
नवयुग में संतुलित इच्छाओं को दरसाए लोहड़ी।
उदय सूरज की पगडंडी लेकर आए लोहड़ी।
बेटियों के लिए दुल्ला–भट्टी की ना हो ज़रूरत।
परम पिता की नेक कमाई में ना हो फिर गुरबत।
आंगन में ऋषियों–मुनियों की भांति समझाए लोहड़ी।
उदय सूरज की पगडंडी लेकर आए लोहड़ी।
माघ महीने की संक्रांति मधुर सुहानी होती।
फसलों की खुशहाली ऊपर खूब जवानी होती।
माघ की प्रथम रात का मौसम परवान चढ़ाए लोहड़ी।
उदय सूरज की पगडंडी लेकर आए लोहड़ी।
कुटुंब भीतर उद्धांगिनी एक धुरी है नारी।
जिसके कारण सुन्दर लगती है यह सृष्टि सारी।
मातृ भूमि में फिर आत्म विश्वास बनाए लोहड़ी।
उदय सूरज की पगडंडी लेकर आए लोहड़ी।
नवयुग में विज्ञान सिखाए नवजीवन में जीना।
शुद्धता बुद्धता सुखद अदाएं परिश्रम बीच पसीना।
भव्य अलौकिक सुषमा भीतर गीत सुनाए लोहड़ी।
उदय सूरज की पगडंडी लेकर आए लोहड़ी।
रेवड़ी, गचक, गन्ने का रस, साग सरसों का, माखन।
तंदूरी रोटी, मांह की दाल रस से खाए साजन।
परदेशों से रिश्तों को हर वर्ष बुलाए लोहड़ी।
उदय सूरज की पगडंडी लेकर आए लोहड़ी।
खर्चीले आयोजन छोड़कर शुद्ध त्यौहार मनाएं।
अमृत महोत्सव के साथ बालम अच्छे कर्म कमाएं।
भारत मां की प्रतिभा–प्रतिष्ठा सांझ बढ़ाए लोहड़ी।
उदय सूरज की पगडंडी लेकर आए लोहड़ी।

बलविन्दर बालम गुरदासपुर
ओंकार नगर गुरदासपुर (पंजाब)
9815625409

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर
"पत्रकारों की आवश्यकता"
'सबका जम्मू कश्मीर' हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र
के लिए जम्मू कश्मीर के सभी जिला के लिए पत्रकारों की आवश्यकता है इच्छुक पत्रकार संपर्क करें
योग्यता:
- पत्रकारिता में अनुभव
- उत्कृष्ट लेखन और संपादन कौशल
- सोशल मीडिया घराने में काम करने का अनुभव
अपना बायोडाटा ई.मेल करें
sabkajammukashmir@gmail.com
संपर्क नंबर :
6005134383

नाम परिवर्तन, तहसीलदार नोटिस, शोक संदेश, गुमशुदा सूचना, बेदखली, हुडा नोटिस, वैवाहिक, सार्वजनिक सूचना इत्यादि विज्ञापन
MOB:- +91 60051-34383, +91 87170 07205

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

एमएलए राजीव जसरोटिया ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से की मुलाकात, जसरोटा क्षेत्र के सड़क व रेल प्रोजेक्ट उठाए

सबका जम्मू कश्मीर

जसरोटा/कठुआ/जम्मू कश्मीर/नई दिल्ली। जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजीव जसरोटिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर अपने क्षेत्र की प्रमुख सड़क और रेलवे परियोजनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने जिला कठुआ के जसरोटा क्षेत्र में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, रेलवे अंडरपास और रेलवे विस्तार से जुड़ी मांगों को लेकर एक लिखित ज्ञापन सौंपा। विधायक ने एनएच राजबागदृमहानाल सड़क (लगभग 23 किलोमीटर) को धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताया। यह सड़क जसरोटा माता मंदिर, चरण कमल गुरुद्वारा और शिव गुफा महानाल जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को

जोड़ती है। उन्होंने कहा कि सड़क संकरी और जर्जर होने के कारण आए दिन जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इस सड़क के चौड़ीकरण और सुधार के लिए उन्होंने केंद्रीय सड़क निधि के तहत करीब 50.46 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी देने की मांग की। इसके साथ ही विधायक ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत डिंगा अंब, बरनोटी और कीरियां गंडयाल ब्लॉकों में प्रस्तावित आठ ग्रामीण सड़कों को जल्द स्वीकृत करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि इन सड़कों के बनने से ग्रामीण इलाकों में आवागमन आसान होगा और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी।

राजीव जसरोटिया ने रेलवे लेवल क्रॉसिंग से होने वाली परेशानी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने एनएच राजबागदृजसरोटा, बरनोटीदृबुढ़ी, लोगेट मोड़दृलोगेट और घत्ती मोड़दृघत्ती औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे अंडरपास बनाने की मांग की, ताकि लोगों को जाम और हादसों से राहत मिल सके।

इसके अलावा उन्होंने कठुआ, बिलावर, बसोली, बनी और भद्रवाह को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रस्तावित नई रेलवे परियोजना पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का पहला चरण तकनीकी रूप से संभव पाया गया है। विधायक ने मांग की कि इस परियोजना के पहले और दूसरे चरण को प्राथमिकता दी जाए।

विधायक ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इन सभी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाएगी, जिससे जसरोटा क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास को गति मिलेगी।

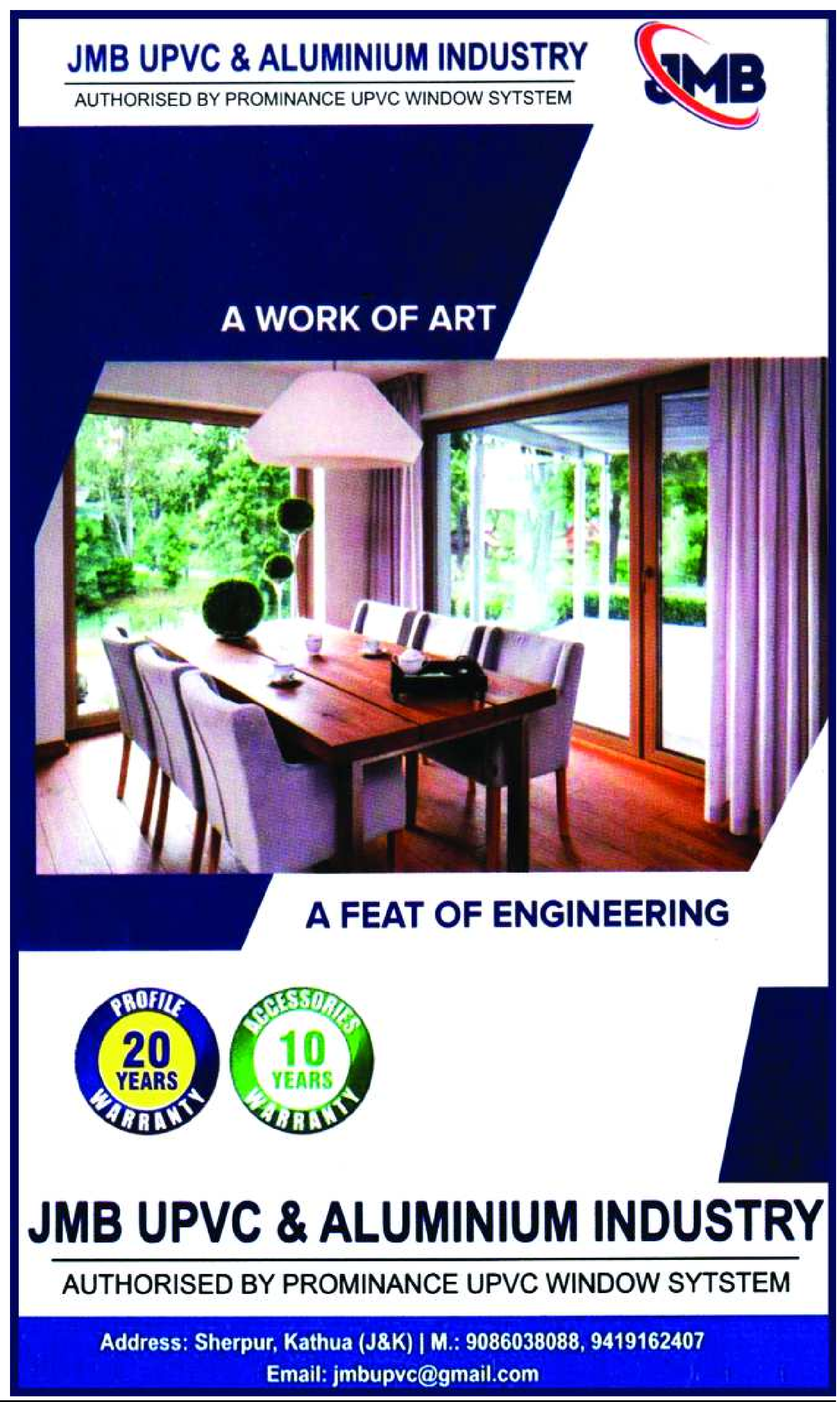

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशकः राज कुमार द्वारा एम/एस डी. आर प्रिंटिग प्रेस, बैन बजाल्ता, तहसील जम्मू से मुद्रित एवं नगरी पैरोल नगरी, जिला कठुआ, जम्मू और कश्मीर पिन.कोड नं: 184151 । संपादकः राज कुमार